CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-274
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, बुधवार 08 जनवरी 2025

आज का विचार

संघर्ष से ना घबराये कुछ पाना है तो धीरे - धीरे ही पा सकते है ।

तिब्बत से भारत तक जलजला... कुछ ही घंटों में 150 बार कांपी धरती, भूकंप से 1000 से अधिक घर जमींदोज,126 से ज्यादा की मौत

मंगल के दिन 'अमंगल'

ल्हासा। तिब्बत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। डिंगरी काउंटी इलाके में आए इस भूकंप में 126 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक घायल हैं। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राहत-बचाव कार्य जारी है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, भूकंप के बाद ऑफ्टरशॉक्स आए। कुछ ही घंटों में 4.4 तीव्रता के साथ 150 बार धरती कांपी। भूकंप और फिर ऑफ्टरशॉक्स जिस इलाकों में आए, वहां की आबादी 6900 है। यहां 1000 से अधिक घर जमींदोज हो गए। दूर-दूर तक हर ओर तबाही देखी जा सकती थी। भूकंप मंगलवार सुबह 9.05 बजे (चीन के समयानुसार) आया। इसका केंद्र डिंगरी काउंटी के त्सोगो टाउनशिप में 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर में सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के केंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में 27 गांव हैं और लगभग 6900 लोग रहते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, डिंगरी काउंटी की आबादी 61000 से ज्यादा है। भूकंप के बाद राहत-बचाव कार्य

के लिए 3400 से अधिक बचावकर्मियों और 340 से अधिक चिकित्सा कर्मचारियों को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है।

नेपाल में हिले बिजली के खंभे और पेड़ भूकंप के झटके नेपाल में भी महसूस किए गए। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भागे। नेपाल के कई जिलों में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। काठमांडू के लोग काफी दहशत में आ गए। सड़क पर बिजली के खंभे और पेड़ हिलते हुए देखे गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, नेपाल में सुबह 7 बजे के लगभग 4 से 5 तीव्रता के 6 से अधिक झटके आए। इन भूकंप के झटकों ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप की याद ताजा कर दी, जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हुई थी।

बिहार, असम, बंगाल और सिक्किम में भी धरती डोली भूकंप का असर भारत में भी देखा गया। बिहार, असम, बंगाल और सिक्किम में भी धरती डोली। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर और सारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बंगाल के मालदा और कुछ और इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। तिब्बत में रुक-रुककर भूकंप के झटके आ रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मैं शौचालय में था, मैंने देखा कि दरवाजा हिल रहा था। भूकंप महसूस होते ही मैं जल्दी से नीचे खुली जगह पर आ गया। मेरी मां भी डर गई थी।

ग्रेट हिमालय बना टाइम बम भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बने हिमालय क्षेत्र में ऐसी भूकंपीय गतिविधि आम है। नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक पर स्थित है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट प्रति वर्ष लगभग 5 सेमी की दर से उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट को धकेलती है। यह हलचल न केवल हिमालय के पहाड़ों को ऊपर उठाती है, बल्कि पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक तनाव भी पैदा करती है। जब संचित तनाव चट्टानों की ताकत से अधिक हो जाता है, तो यह भूकंप के रूप में निकलता है। यही कारण है कि नेपाल और उसके आस-पास के हिमालयी क्षेत्र में अक्सर भूकंपीय गतिविधि होती रहती है। नेपाल की जमीन की ऊपरी परत अस्थिर चट्टानों से बनी है, जो भूकंप के प्रभावों को बढ़ाती है, जिससे यह और भी कमजोर हो जाती है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी सरकार, मोदी से मिली शर्मिष्ठा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय स्मृति' परिसर (राजघाट परिसर का एक हिस्सा) के भीतर एक स्थल को चिन्हित करने को मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि, इसकी जानकारी लेखक और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के उनके सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त की। यह और भी अधिक सराहनीय है, क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित लेकिन सचमुच दयालु भाव से मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा- बाबा कहते थे कि राजकीय सम्मान के लिए मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पेश करना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की याद में ऐसा किया। इससे बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब कहां हैं- सिर्फ तारीफ या आलोचना से परे। लेकिन उनकी बेटी के लिए, मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

मक्का और मदीना में आई बाढ़, पूरा सऊदी अरब हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली। सऊदी अरब का जब जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में मक्का, मदीना और रेगिस्तान की तस्वीर बनती है। लेकिन अब यहां के हालात बदल गए हैं। भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई है। मक्का और मदीना के ज्यादातर हिस्सों में खास तौर से जेद्दा शहर और गवर्नरेट के अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफान के साथ भारी बारिश हुई। बारिश के बाद आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बारिश बुधवार को भी जारी रह सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही

तस्वीरों में शहर आंशिक रूप से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब में मक्का मदीना बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां दुनियाभर से हर वर्ष लाखों मुसलमान हज और उमरा करने के इन शहरों में आते हैं। मगर इन दिनों भयंकर बारिश ने पूरे सऊदी का माहौल बदल दिया है। भारी बारिश के कारण सऊदी के कई शहर डूब गए हैं। आगे भी ऐसी स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। आपातकालीन सेवाएं किसी भी घटना के जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार स्थिति को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं, मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रहेगी।

खराब सेहत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दी आसाराम को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू जल्द जेल से बाहर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। वह केवल चिकित्सा आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा। आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने कई बार स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने की याचिका दायर की थी

दिल्ली में बजा चुनावी बिगुल

5 फरवरी को वोटिंग, 8 को काउंटिंग

नई दिल्ली। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का एलान मंगलवार को हो गया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे साथ ही 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तारीखों के एलान से पहले ही सभी प्रमुख पार्टियों ने चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी तरह भाजपा अब तक 29 और कांग्रेस 47 उम्मीदवारों का एलान कर चुकी है। इस बार यह मुकाबला तीन बड़े दलों- सत्तासीन आम आदमी पार्टी, विपक्षी भाजपा और पिछले चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच हो रहा है। तीनों ही दल अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीटें लाने का दावा कर रहे हैं।

दिल्ली में बीते 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2013, 2015 और फिर 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने की एक बड़ी वजह है आप पर लगे आरोप। दरअसल, पहले तीन चुनावों में आप ने दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभाला। हालांकि, इस बार पहले शराब घोटाला उसके बाद मुख्यमंत्री बंगले के रेनोवेशन से जुड़े आरोप सामने आने के चलते केजरीवाल एंड कंपनी की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में कद्दावर नेताओं का नाम देकर यह साबित कर दिया है कि वह इस चुनाव में किसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहतीं। इस बीच यह जानना अहम है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दों का असर सबसे ज्यादा रहेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उसके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जिसके चलते बीते तीन से चार वर्षों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेताओं को जेल तक जाना पड़ा है। इनमें सबसे बड़े आरोप रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला केस से जुड़े आरोप, जिन्हें लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आप पर हमलावर रहे हैं।

यूजीसी ने मप्र सरकार को दिए फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश

भोपाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एनएसयूआई की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश में संचालित फर्जी निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यूजीसी ने अपने पत्र में एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा किए गए शिकायती पत्र का उल्लेख किया। शिकायत में उन्होंने बताया था कि राज्य में शिक्षा माफियाओं द्वारा संचालित फर्जी निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों की जांच करे और उपयुक्त कार्रवाई के बाद पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे। शिकायती पत्र में कहा गया है कि राज्य के 70त्न से अधिक निजी विश्वविद्यालय केवल कागजों पर संचालित हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में न तो नियमानुसार स्टाफ है और न ही मानक भवन। हाल ही में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में योग्य कुलपति नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। कई विश्वविद्यालय फर्जी पते पर संचालित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, छात्रों का प्रवेश भोपाल के नाम पर लिया जाता है, लेकिन कॉलेज रायसेन, विदिशा या सीहोर में चलता है। कुछ विश्वविद्यालय डिग्री बेचने का गोरखधंधा भी कर रहे हैं। छात्रों के प्रवेश का कोई समय निर्धारित नहीं है, और सत्र में सालभर दाखिले लिए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं से निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अटेंडेंस लेट फीस के जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली की जा रहीं जो विवि में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं हैं।

राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं

नई दिल्ली। फ्रीबीज मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त धन है, जो कोई काम नहीं करते हैं। मगर, जब जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का हवाला देते हैं। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने देश के अटॉर्नी जनरल की दलील के जवाब में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र सरकार की लाडली-बहना योजना और राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों का हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य के पास ऐसे लोगों के लिए पैसा है जो कोई काम नहीं करते हैं। जब हम वित्तीय बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए।

वित्तीय बोझ की चिंताओं को ध्यान में रखें कोर्ट ने कहा कि चुनाव आते ही आप लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं का ऐलान करते हैं। इन योजनाओं में आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में किसी न किसी पार्टी की ओर से घोषणाएं होती हैं। राजनीतिक दल कहते हैं, अगर वो सत्ता में आए तो 2500 रुपये देंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ्रीबीज कल्चर को एक विचलन माना जा सकता है। वित्तीय बोझ की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पहले भी चिंता जता चुका है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने के दौरान की। कोर्ट इस बात पर पहले भी चिंता जता चुका है कि देश में जिला न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन दरें बहुत कम हैं।

सिंहस्थ-2028 की मंत्रिमंडलीय समिति की दूसरी बैठक

सिंहस्थ के लिए 1451 करोड़ के नए कामों को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को सिंहस्थ-2028 की मंत्रिमंडलीय समिति की दूसरी बैठक की। गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 1451 करोड़ रुपये लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर खंडवा सहित उज्जैन, खंडवा, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना, ट्रांजिट हॉस्टल व कैंप, बैरक आदि शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन और इंदौर संभाग में जारी अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण किया जाए और निर्माण एजेंसियों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिन में उच्च स्तर से समन्वय या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के संज्ञान में लाए जाएं। निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

इंदौर और उज्जैन में बस अड्डों का विकास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर और उज्जैन जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि और नवीन बस अड्डों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना मार्च-2025 तक तैयार की जाएगी। सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रयागराज कुंभ और हरिद्वार कुंभ मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।

सब्जी किसानों का बुरा हाल, टमाटर और गोभी के नहीं मिल रहे दाम

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर और आसपास के सब्जी किसानों का इस समय बुरा हाल है। उन्हें टमाटर और गोभी के दाम नहीं मिल रहे हैं। गोभी के दाम नहीं मिलने पर इसे जानवरों को खिलाया जा रहा है। ज्यादा बोवनी से अधिक उत्पादन हुआ है और बादलों के बने रहने के कारण समय के पहले एक साथ पक जाना इसका बड़ा कारण है। गोभी के दाम नहीं मिलने पर किसानों ने इन्हें काटकर मंडी में नहीं ले जाने का फैसला किया है। किसानों ने अपनी फसल जानवरों को खिलाना आरंभ कर दिया है। अचानक हुई वर्षा और बादलों के आने के चलते गोभी की बहुतायत हो गई और किसान इसे जानवर को खिलाने पर मजबूर हो गए। गोभी के दाम 2 से 3 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिल रहे और इसकी कटाई और मंडी तक ले जाने का खर्च ज्यादा पड़ रहा है। उधर, टमाटर की जोरदार आवक होने और टोमेटो कैचअप बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फैक्ट्री मालिकों द्वारा खरीदी करने से कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। आगे और भी दामों में मंदी की संभावना है। मध्यप्रदेश की आम जनता को आगामी अप्रैल माह तक

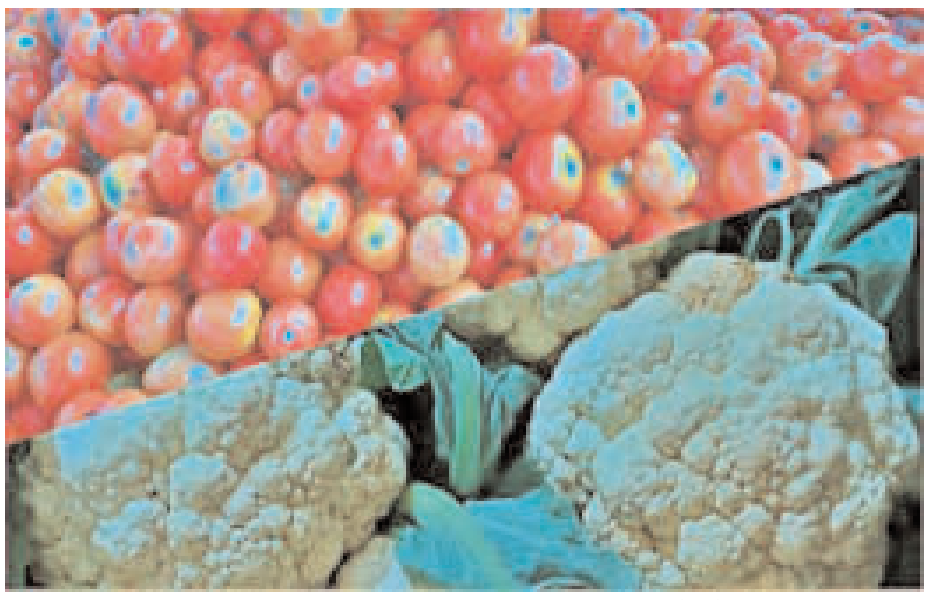

सस्ता टमाटर मिलता रहेगा। यह दावा किसानों और व्यापारियों ने देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी में किया। दरअसल टमाटर की फसल दो प्रकार से लगाई जाती हैं। एक तो जमीन में सीधे और दूसरे तार और बांस-बल्लियों पर बेल को चढ़ाया जाता है। जमीन पर फसल लगाने वाले किसानों को लागत कम लगती हैं, लेकिन यह टमाटर जल्दी खराब होता है। स्टोरेज में भी दिक्कत रहती है इसलिए इसकी मांग फिलहाल कम है। जमीन से ऊपर लगाने वाला टमाटर लंबे समय तक चलता है।

गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, तुड़ाई खर्च पूरा करने में मुश्किल

टमाटर के दाम कम होने से किसानों को गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, तुड़ाई खर्च पूरा करने के लिए मुश्किलें आ रही हैं। मंगलवार को भाव और गिरकर 100 से 150 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गए। आवक 7 से 8 हजार कट्टों की बताई गई। क्वालिटीनुसार 6 से 8 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खरगोन के किसान अशोक वर्मा, भूपेंद्र वर्मा, जीतू बागड़ी, शुभम नेकिये ने दावा किया कि मध्यप्रदेश की आम जनता के घरों, ढाबों, होटलों में गर्मियां शुरू होने से पहले अप्रैल माह तक सस्ता टमाटर मिलता रहेगा। फिलहाल किसानों का गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, तुड़ाई, बीज, दवाई, खाद खर्च निकलने में मुश्किलें आ रही हैं।

मंडी में लाकर बेचना मजबूरी

किसानों का कहना है कि टमाटर के एक कैरेट पर 80 से 90 रुपए लागत आती है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते है, माल तो मंडी में लाकर बेचना ही होगा, नहीं तो खेतों में खराब हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल-मई में महाराष्ट्र से नए टमाटर की आवक शुरू होगी। उसके बाद ही कीमतों में इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि गर्मियों में आवक 2 से 3 हजार कट्टे की ही होती है। ठंडे मौसम में टमाटर की खपत कम होती है, क्योंकि हरी सब्जियों की भरपूर आवक होती हैं।

यहां से हो रही टमाटर की आवक

व्यापारी फारुख राइन ने बताया कि इंदौर के आसपास के क्षेत्र महेश्वर, मंडलेश्वर, खरगोन, राजगढ़-धार, सेंधवा के पास नागलवाड़ी, बलवाड़ी गांव से लोकल में देसी, हाईब्रिड, हिम सोना किस्म के टमाटर की जबरदस्त आवक हो रही हैं। वहीं, राजस्थान में भीलवाड़ा, जयपुर, चोमू, मप्र के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और यूपी के झांसी में बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों के आसपास की मंडियों में आवक हो रही हैं। इससे इंदौर की चोइथराम मंडी से टमाटर की खपत नहीं हो रही हैं, जिससे इंदौर के आसपास के टमाटर की खपत यही हो रही हैं। टमाटर व्यापारी इकबाल राइन, फारूक राइन, विनोद भिलवारे के मुताबिक मई से लेकर अक्टूबर तक 1500 से 2000 हजार रुपए प्रति कैरेट तक भाव पहुंच गए थे। नवंबर-दिसंबर में ठंड शुरू होते ही जोरदार आवक होने से दाम और 500 से 700 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गए। अब जनवरी में दाम औंधे मुंह गिर पड़े और 150 से 200 रुपए प्रति कैरेट तक आ पहुंचे। मंगलवार को भाव और गिरकर 100 से 150 रुपए प्रति कैरेट (1 कैरेट में 25 किलो) तक पहुंच गए। आवक 7 से 8 हजार कट्टों की बताई गई।

पत्ता गोभी के 5 रुपए किलो भी नहीं मिल रहे दाम

बड़वानी के किसान रामलाल ने बताया कि उन्होंने दो एकड़ क्षेत्र में पत्ता गोभी लगाई थी लेकिन फसल अच्छी होने के बावजूद 5 किलो भी दाम नहीं मिल रहे तो इसे मवेशियों के हवाले कर दी। पौधे खरीदने से लेकर इसे लगाने खाद व कीटनाशक व मजदूरी देने में करीब 50000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। गोभी की फसल को काटने और उसे मंडी तक ट्रांसपोर्ट करने का खर्च उसे उगाने से ज्यादा पड़ रहा है। मंसाराम व राजपुर क्षेत्र के अन्य किसानों धन्नालाल कुशवाहा, मनोहर और रमेश आदि ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हुई बरसात और बादलों के लगातार बने रहने के चलते गोभी तेजी से पक गई। एक साथ ढेर सारी गोभी बाजार में आने से इसके दाम जमीन पर आ गए। सेंधवा क्षेत्र के सब्जी नीलाम करने वाले करण वर्मा ने बताया कि बादलों के चलते गोभी तेजी से पक गई, और चार से पांच रुपए किलो ही बिकी। बड़वानी के किसान मनीष कुशवाहा ने बताया कि इस बार किसानों ने जरूरत से ज्यादा गोभी की बोवनी कर दी। इस बार बड़े किसान भी मैदान में आ गए थे। पैदावार ढेर सारी हो गई और खपत उतनी ही बनी रही, इसके चलते यह हाल हो रहे हैं।

सब्जियों का भी हो समर्थन मूल्य

किसानों ने कहा कि अनाज की तरह सब्जियों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में नुकसान न हो। किसानों ने बताया कि दरअसल किसान को जिस फसल में ज्यादा लाभ दिखाई देता है, वह उसे बहुतायत में लगा लेते हैं। इसकी पैदावार ज्यादा हो जाने के चलते यह स्थिति बनती है।

धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने वाले दंपति का पर्दाफाश

हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किया पुलिस के हवाले, केस दर्ज

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने एक दंपति को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला मजदूर परिवार की महिला गौरीबाई की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि दंपति उसे और उसके परिवार को ईसाई धर्म अपनाने के लिए रुपए और नौकरी का लालच दे रहे थे। हिंदू जागरण मंच के संयोजक राजकुमार टेटवाल और मानसिंह राजावत को स्कीम नंबर 136 में धर्मांतरण गतिविधि की सूचना मिली थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने मजदूर परिवार से बात की और जॉनी नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी शैली को पकड़ लिया। मानसिंह राजावत ने बताया कि दंपति को पुलिस को सौंप दिया है। जॉनी और शैली ने पूछताछ के दौरान खुद को केरल का निवासी बताया और यह स्वीकार किया कि वे धर्मांतरण का काम करते हैं। हिंदू जागरण मंच के संयोजक राजकुमार ने बताया कि दंपति ने मजदूर परिवार को 6 लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था।

अलीराजपुर की गौरीबाई पर बना रहे थे दबाव

गौरीबाई, जो मूल रूप से जोबट, अलीराजपुर की निवासी है, ने पुलिस को बताया कि वह इंदौर में काम की तलाश में आई थी। जॉनी और शैली स्कीम नंबर 136 में किराये के मकान में रहते थे और एक साल पहले उनसे संपर्क किया था। दोनों ने धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से बातचीत शुरू की और ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक स्थिति सुधारने और अच्छी

नौकरी का वादा किया। सोमवार शाम को जॉनी और शैली उनके घर आए और प्रवचन देने के साथ उनके बेटे और बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने लगे। जब इस घटना की जानकारी अन्य लोगों को हुई, तो उन्होंने दंपति को रोका और हिंदू जागरण मंच को सूचना दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर जॉनी पुत्र जॉर्ज और उसकी पत्नी शैली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

महिला की शिकायत पर केस दर्ज

मजदूर परिवार की महिला गौरीबाई की शिकायत पर पुलिस ने जॉनी पुत्र जॉर्ज (निवासी सेटेलाइट जंक्शन, लसूडिया) और उसकी पत्नी शैली के खिलाफ मामला दर्ज किया। गौरीबाई ने बताया कि वह जोबट, अलीराजपुर की रहने वाली है और इंदौर में काम की तलाश में आई है। उनके अनुसार, जॉनी और शैली स्कीम नंबर 136 में किराये पर रहते थे और एक साल पहले उनके साथ धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों पर चर्चा करने लगे थे।

गौरीबाई ने आरोप लगाया कि जॉनी और शैली ने ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक स्थिति में सुधार और अच्छी नौकरी का वादा किया था। सोमवार शाम को वे उनके घर आए और धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रवचन देने लगे। उन्होंने उनके बेटे और बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और कुछ धार्मिक पुस्तकें और मंत्रों का जाप करवाया। जब यह बात अन्य लोगों को पता चली, तो उन्होंने दंपति से पूछताछ की और मामले की जानकारी पुलिस को दी।

लवकुश फ्लायओवर की दूसरी भुजा भी तैयार, जल्द होगी ट्रैफिक के लिए शुरू

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण ने लवकुश चौराहा पर जो फोरलेन फ्लायओवर बनाया है उसकी एक भुजा से तो कुछ समय पूर्व यातायात शुरू कर दिया था, अब दूसरी भुजा भी तैयार हो गई है और आज-कल में इस पर से भी यातायात दौडऩे लगेगा। इस फ्लायओवर पर प्राधिकरण ने 68 करोड़ की राशि खर्च की है और इसी लवकुश चौराहा पर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लायओवर भी 150 करोड़ रुपए की लागत से प्राधिकरण द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है। इस फ्लायओवर के शुरू होने से लवकुश चौराहा पर होने वाले यातायात जाम से भी लगभग मुक्ति मिल गई है और अब सुपर कॉरिडोर, एयरपोर्ट जाना-आना आसान हो गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा चार चौराहों पर फ्लायओवरों की सौगात दी गई है, जिसमें फूटी कोठी और भंवरकुआ का फ्लायओवर तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लोकार्पित कर दिया गया और उसके साथ खजराना तथा लवकुश की भी एक-एक भुजा से यातायात शुरू कर दिया था। अभी पिछले दिनों खजराना फ्लायओवर की दूसरी भुजा से भी यातायात शुरू हो गया है और अब उसी तर्ज पर लवकुश चौराहा के फ्लायओवर की दूसरी भुजा से भी आज-कल में यातायात दौडऩे लगेगा। दरअसल पूर्व में एमआर-10 से सुपर कॉरिडोर जाने वाली भुजा से यातायात शुरू किया गया था और अब सुपर कॉरिडोर या एयरपोर्ट की तरफ से आने वाली भुजा भी तैयार हो गई है। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक साफ-सफाई सहित आज यह देखा जाएगा कि कहीं कुछ बाधा तो नहीं है।हालांकि रात में लाइटिंग का भी परीक्षण कर लिया गया है और आज-कल में ही यह भुजा भी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ डबल डेकर फ्लायओवर का काम भी तेज गति से चल रहा है। हालांकि अगले 6 महीने तक उस पर सेगमेंट लॉन्चिंग का कार्य ही चलेगा। पिछले दिनों इसकी भी विधिवत शुरू की गई। वहीं प्राधिकरण एबी रोड पर भी फ्लायओवरों की संभावना के मद्देनजर फिजिबिलिटी सर्वे करवा रहा है। बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है। हालांकि उस पर अभी न्यायालय की सहमति बाकी है, मगर एलआईजी चौराहा से लेकर पलासिया, गीताभवन और नवलखा के बीच फ्लायओवरों का निर्माण किया जाना है। फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन-किन चौराहों पर फ्लायओवर निर्मित किए जा सकते हैं। इसके अलावा 11 अन्य चौराहों पर भी फ्लायओवर की संभावनाएं तलाशी गई है। पिछले दिनों बड़े गणपति फ्लायओवर का भी भूमिपूजन करवाया गया। महूनाका के लिए अवश्य मास्टर प्लान में सडक की चौड़ाई बढ़ाने की मांग शासन से की गई है, जो अभी तक लम्बित है। दूसरी तरफ केबल कार का फिजिबिलिटी सर्वे भी प्राधिकरण ने करवाया है और किन रुटों पर इसे चलाया जा सकता है उस पर भी विचार-विमर्श जारी है।

पार्षद कालरा के समर्थन में सिंधी समाज पहुंचा भाजपा कार्यालय

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा और जीतू यादव के बीच चल रहे विवाद में अब समाज भी कूद गया है। दो दिन पहले जीतू यादव और निगमकर्मी यतींद्र यादव के साथ यादव समाज के लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे तो मंगलवार को सिंधी समाज के पदाधिकारी भाजपा कार्यालय पहुंचे और जीतू यादव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। कुछ समाजजनों ने कहा कि यादव ने कालरा की मां और बेटे को मारा है। यदि संगठन कठोर रवैया नहीं अपनाता है तो सिंधी समाज के लोग भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों को शोकाज नोटिस दिया गया है। जांच के बाद संगठन एक्शन लेगा। सिंधी समाज के लोग पुलिस अफसरों से भी मिले और दर्ज किए गए प्रकरण के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सिंधी कॉलोनी में व्यापारियों ने दुकानें भी बंद रखी। भाजपा कार्यालय में पार्षद कमलेश कालरा अपनी मां, बच्चे और पत्नी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने घर पर हुए हमले की रिकार्डिंग भी सौंपी। बता दें, कुछ दिनों पहले पार्षद कालरा और निगम कर्मी की कॉल रिकार्डिंग वायरल हुई थी। इसमें कालरा निगमकर्मी के धमकाए जाने पर जीतू यादव के खिलाफ बोले थे। इसके बाद उनके घर पर हमला हो गया था। कालरा ने हमले का आरोप जीतू यादव पर लगाया है। एमआईसी मेंबर जीतू यादव ने कहा कि कालरा बेवजह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वे चार नंबर विधानसभा के पार्षद हैं, इसलिए विधायक मालिनी गौड़ उन्हें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष से मिलवाने ले गईं। मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे साथ भी खड़ी रहेंगी। यदि मैं कुछ गलत करता हूं तो वे मुझे डांटने का भी हक रखती हैं।

हटाए जाने वाले बीआरटीएस की बस लेन में हो रहा डामरीकरण

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में 300 करोड़ की लागत से बने बीआरटीएस को हटाने का फैसला सरकार ने किया है। बीआरटीएस के चौराहों पर नगर निगम ब्रिज बनाएगा। इसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे भी हो चुका है, लेकिन तोड़ने के फैसले के बावजूद बीआरटीएस पर लाखों रुपये खर्च भी किए जा रहे है। इसे लेकर लोग भी आश्चर्यचकित है। बीआरटीएस की बस लेन में सोमवार को नगर निगम कुछ हिस्सों में डामरीकरण करा रहा है। पलासिया, एलआईजी चौराहे पर बस लेन में श्रमिकों ने दिनभर डामरीकरण का काम किया।दो माह पहले इंदौर में हुई यूरेशियन समूह की बैठक के समय भी बीआरटीएस की बस लेन की रैलिंग पर कलर पेंट किया गया। लोगों का कहना है कि जब बीआरटीएस को तोड़ने का फैसला सरकार ले ही चुकी है तो फिर उसमें नए सिरे से काम क्यों कराए जा रहे है। इस बारे में जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर का कहना है कि बसों का संचालन मार्ग पर जारी रहेगा। जहां गड्ढे हो चुके है। वहां पेचवर्क किया जा रहा है। बीआरटीएस का सबसे पहला प्रोजेक्ट देश में इंदौर शहर में स्वीकृत हुआ था। केंद्र सरकार ने इसके लिए 198 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। राज्य शासन ने भी इसमें राशि मिलाई थी। इंदौर के अलावा भोपाल में भी बीआरटीएस बना था, लेकिन उसे तोड़ा जा रहा है। इंदौर का बीआरटीएस प्रोजेक्ट सफल साबित हुआ है। इसके बावजूद उसे तोड़ने का फैसला लिया गया है।

नागरिकों की सलाह से तय होगी इंदौर के विकास की रूपरेखा

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में वर्ष 2047 को दृष्टिगत रखते हुए जिला, शहर और विधानसभा स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों के सुझाव लेने के लिए जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन जनसंवाद कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला आज से प्रारंभ हुआ। इस कड़ी का पहला जनसंवाद कार्यक्रम रविन्द्र नाट्य गृह में सम्पन्न हुआ। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने एवं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से

विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुई नागरिकों की आकांक्षाओं, विचारों और प्राथमिकताओं को विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा।

यह बोले महापौर पुष्यमित्र भार्गव

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 तक अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी रूप से शामिल हो। प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर भी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदौर विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा। प्रदेश विकसित होगा तो देश भी विकसित बनेगा। हम इंदौर को तेजी से विकसित इंदौर की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। इस विकास यात्रा में सभी प्रबुद्धजनों का सहयोग और सुझाव आमंत्रित है। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न प्रबुद्धजनों अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

राज्य स्तर पर जाएंगे फीडबैक

कार्यक्रम का संचालन स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह ने किया। जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से फीडबैक संकलित कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। तैयार किए जा रहे विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को जिलों के साथ साझा किया जाएगा। इस प्रारूप के आधार पर प्रत्येक जिला मध्यप्रदेश के समग्र विजन के साथ सरेखित अपना जिला स्तरीय विजन डाक्यूमेंट तैयार कर सकेगा। यह प्रक्रिया जिलों की विशेषताओं, प्राथमिकताओं और संभावनाओं को शामिल करते हुए समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगी।

जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने सुने सुझाव

इस जनसंवाद कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर सहित इंदौर नगर निगम के महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, शहर के प्रबुद्धजन, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

महिला की मौत के 7 माह बाद काटजू अस्पताल के अधीक्षक समेत 5 पर केस

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल में लापरवाही की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। यहां पर 7 महीने पहले एक महिला की जान चली गई थी। जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। अब 7 महीने बाद अस्पताल के अधीक्षक सहित 5 पर टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मृतका अस्पताल में नसबंदी के लिए आई थी। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया था कि अस्पताल में बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन किया गया। जिसके चलते महिला की मौत हुई। टीटी नगर पुलिस ने, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा जैन, काटजू अस्पताल के अधीक्षक कर्नल पीके सिंह, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट

जीएमसी डॉ. केलू ग्रेवाल और पैरामेडिकल स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की है।

वकील अनिल कुमार नामदेव के अनुसार लंबी जद्दोजहद के बाद यह एफआईआर हुई है। प्राइवेट शिकायत पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर पाया कि यह मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। महिला को एनेस्थीसिया दिए बिना ओटी में लेकर गए। वहां उन्हें 1 सेमी का चीरा लगाया। इससे लापरवाही साबित होती है। वह 10 बजे पूरी तरह से स्वस्थ थीं। ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि है वह कोलेप्स हो गई। अभी तक की जानकारी में पाया गया है कि उस समय अस्पताल में दो दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ थे। मगर ओटी में एक भी नहीं गया था। यह आईएमए की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

14 मई 2024 का है मामला

यह मामला 14 मई 2024 का है। सिवनी मालवा निवासी रीना गौर (38) नसबंदी ऑपरेशन के लिए काटजू अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। रीना के पति अविनाश गौर के मुताबिक ऑपरेशन से पहले रीना पूरी तरह स्वस्थ थी। जब उसे थिएटर से बाहर लाया गया तो उसका पेट फूला हुआ था। डॉक्टरों और स्टाफ ने गलत जानकारी दी और कहा कि ऑपरेशन के दौरान अटैक आने से रीना की मौत हुई है। उस समय मुझसे कई तरह के पेपर भी दबाव बनवाकर साइन करवाए गए। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मना कर दिया। बाद में बहुत जोर लगाने के बाद बॉडी का पोस्टमॉर्टम हुआ। जिसमें हमने विसरा प्रिजर्व करने की मांग की। वह भी पुलिस और डॉक्टर ने नहीं किए। अविनाश ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की थी।

लंबी जद्दोजहद के बाद एफआईआर

वकील अनिल कुमार नामदेव के मुताबिक लंबी जद्दोजहद के बाद यह एफआईआर हुई है। प्राइवेट शिकायत पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर पाया कि यह मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। महिला को एनेस्थीसिया दिए बिना ओटी में लेकर गए। वहां उन्हें 1 सेमी का चीरा लगाया। इससे लापरवाही साबित होती है। वह 10 बजे पूरी तरह से स्वस्थ थीं। ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि है वह कोलेप्स हो गई। अभी तक की जानकारी में पाया गया है कि उस समय अस्पताल में दो दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ थे। मगर ओटी में एक भी नहीं गया था। यह आईएमए की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए मिलेगी ट्रेनिंग

मप्र में आज से शुरू होगी पार्थ योजना, सीएम करेंगे शुरुआत

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खेल एवं युवा विभाग की तरफ पार्थ योजना की शुरुआत होने जा रही है। पार्थ योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें युवाओं को फीजिकल और प्रैक्टिल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत आठ जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। दरअसल, मध्य प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम लोग युवा कल्याण के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या युवा आर्मी और पुलिस की तैयारी करते हैं। इसे देखते हुए पार्थ योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी और पुलिस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फिजिकल के साथ-साथ उन्हें टेस्ट की तैयारी भी कराई जाएगी।

अभी संभागीय स्तर पर तैयारी

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस योजना की शुरूआत अभी संभागीय स्तर पर होगी। संभाग स्तर पर हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन जगहों पर प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनर भी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेंड करने के लिए हमारे एक्सपर्ट होंगे।

मामूली शुल्क भी लगेगा

हालांकि युवकों को यह ट्रेनिंग फ्री में नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि संभागीय स्तर पर दाखिले की सीमा अभी तय नहीं हुई है। व्यवस्थाओं के आधार पर फैसला होगा। हालांकि हम छात्रों की लिमिट अभी तय नहीं करेंगे। अधिक से अधिक छात्रों को समाहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए छात्रों से एक मामूली राशि भी ली जाएगी। वहीं, यह राशि कितनी होगी, यह तय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यूथ पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर छात्र अपनी जानकारी अपलोड करेंगे।

दो योजनाओं का शुभारंभ होगा

मंत्री सारंग ने बताया कि टीटी नगर स्टेडियम में 28वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव चल रहा है। इसका बुधवार को समापन होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री खेल विभाग की पार्थ योजना और व एमपीवायपी (मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान) का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

12 जनवरी को पीएम के सामने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे युवा

टीटी नगर स्टेडियम में युवा उत्सव चल रहा है। इसमें 7 विधा की प्रतियोगिता हो रही है। इन विधा में समूह लोक गीत, समूह लोक गायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन और कविता लेखन शामिल हैं। प्रदेश के 10 संभाग से 350 प्रतिभागी 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव के विजेता 10-12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव में हिस्सा लेंगे। 12 जनवरी को चयनित टीम नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में सीएम डॉ. यादव शामिल होंगे।

इरफान खान के करीबी वरिष्ठ रंगकर्मी आलोक चटर्जी का निधन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। जाने-माने थिएटर अभिनेता आलोक चटर्जी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। सोमवार रात 12 बजे भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह मध्यप्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा(टढरऊ) के पूर्व निदेशक भी थे। अभिनेता ओम पुरी के बाद एनएसडी (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार रहे इरफान खान से भी आलोक चटर्जी की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साल 1984 से लेकर 1987 तक एक साथ पढ़ाई की। दोनों ने तीन साल तक नाटकों में लीड रोल भी निभाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड से सम्मानित किया था। चार दिन बाद (11 जनवरी) उनका जन्मदिन आने वाला था। रंगकर्मी बालेंद्र बालू ने बताया कि सोमवार रात करीब 11-12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह कई बीमारियों से जूझ रहे थे। किडनी पैंक्रियाज में भी समस्याएं थीं। उन्हें बंसल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। इसके चलते उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। भोपाल के रंगकर्मी बालेंद्र सिंह ने बताया कि इरफान खान जब भोपाल में जहांनुमा होटल में एक निजी कार्यक्रम में आए। तब आलोक भाई सिगरेट पी रहे थे और इरफान खान साहब बीड़ी। दोनों ने एनएसडी के दिनों के खूब किस्से सुनाए थे। इरफान खान ने वहां ये बात कही कि मैं बहुत आलसी था। आलोक चटर्जी को देखकर मैने रियलिस्टिक एक्टिंग को जाना। मेरी प्रेम कहानी और शादी कराने में भी आलोक भाई शामिल रहे। मेरा लव लेटर आलोक लिखते थे और मेरा प्रेम का प्रस्ताव लेकर सुतापा जो अब मेरी पत्नी है उसके पास आलोक ही गए थे। मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे आलोक चटर्जी 8वीं कक्षा पास कर जबलपुर चले गए थे। इसके बाद वे भोपाल में बस गए। बाद में उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ड्रामा में डिग्री हासिल की। आलोक चटर्जी एनएसडी से बेस्ट एक्टिंग के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले दूसरे शख्स थे। उनसे पहले दिग्गज फिल्म स्टार ओम पुरी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल मिला था। अपने अंतिम समय में अपने गृहनगर भोपाल में थिएटर कर रहे आलोक चटर्जी को 2019 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड से सम्मानित किया था।

मध्यप्रदेश में अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए बनी कमेटी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के 11 माह बाद राज्य सरकार ने अवैध हथियारों और गोला बारूद पर कंट्रोल के लिए प्लानिंग शुरू की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के कारोबार के जरिए अशांति के हालात बनाने के मद्देनजर राज्य शासन से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। एमपी में पिछले साल हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री विवाद की वजह बनी थी। इसी के चलते प्रदेश में अवैध हथियार और गोला बारूद तैयार कर बेचने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों में कंट्रोल के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी ढाई माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार इस तरह के मामलों में रोक को लेकर निर्देश जारी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसमें कहा गया है कि अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि इस पांच सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह को सदस्य सचिव बनाया गया है। साथ ही समिति के सदस्यों के रूप में पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग और विनय मिश्रा बैलेस्टिक विशेषज्ञ (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) नियुक्त किए गए हैं। समिति 10 सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2024 में इसके आदेश जारी किए हैं और एमपी समेत अन्य राज्यों से दस हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

भोपाल को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की तैयारी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए विख्यात है। इसके मद्देनजर, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस वर्ष 2025 में भोपाल को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल कराने के लिए आवेदन तैयार कर रहा है। बता दें कि वैश्विक पहचान का मंच यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्होंने अपने विकास में रचनात्मकता को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में 350 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं और यह सात रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इनमें शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत शामिल है। भोपाल में साहित्यिक गतिविधियों की समृद्ध परंपरा है। विश्व पुस्तक मेले, साहित्य उत्सव, कवि सम्मेलनों और चर्चित साहित्यिक मंचों की मेजबानी करते हुए, यह शहर साहित्यिक उन्नति का केंद्र बना है। स्थानीय लेखकों, कवियों और साहित्यप्रेमियों की सक्रिय भागीदारी इसे सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। ग्वालियर के बाद भोपाल की बारी 2023 में मध्यप्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इसके बाद भोपाल को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल करने राज्य सरकार और पर्यटन प्रयास कर रहे है.

मप्र टूरिज्म बोर्ड तैयार कर रहा आवेदन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करने के लिए विस्तृत आवेदन तैयार कर रहा है। इसमें शहर की साहित्यिक गतिविधियों, ऐतिहासिक योगदान और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा।

संविदाकर्मियों का धरना 6वें दिन स्थगित, प्रबंध संचालक ने दिया आश्वासन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक राजू रावत के लिखित आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय में 6 दिन से चल रहा धरना स्थगित कर दिया है। संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रबंध संचालक ने बताया कि संविदा कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की नस्थी मंत्रालय पहुंच गई है, इस पर जल्द निर्णय लिया जा रहा है। वहीं अन्य समस्याओं का निराकरण भी जल्द कर देंगे। राठौर ने कहा कि रावत के कहने पर धरना स्थगित किया गया है। बता दें कि ये कर्मचारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 1 जनवरी से धरने पर बैठे थे। राठौर ने बताया कि निगम के प्रबंध संचालक ने मंगलवार को इन कर्मचारियों को चर्चा के लिए बुलाया था और सौहार्द्रपूर्ण चर्चा के बाद धरना स्थगित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निगम के संविदा कर्मचारी संचालक मंडल की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार वेतनवृद्धि की मांग कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने आरजीपीवी के कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने स्थाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कुलगुरु प्रो. राजेंद्र त्रिपाठी को सौंपा। प्रो. त्रिपाठी ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पूरी कराने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मंच का प्रतिनिधिमंडल कुलगुरु से मिला था। उन्हें पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें स्थाईकर्मियों को नियमित करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ देने, अकुशल श्रमिकों का श्रेणी परिवर्तन करने, 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, स्थाई कर्मियों को सरकारी कर्मचारी के समान अवकाश सुविधा का लाभ देने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति देने की मांगों को प्रमुखता के साथ रखा गया है।

कमलनाथ कांग्रेस संगठन से नाराज, कहा- मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरी मीटिंग में कांग्रेस संगठन से नाराजगी जताई है। दरअसल, सोमवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वर्चुअली जुड़े। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, न ही मीटिंग की सूचना दी जाती है। अखबारों से पता चलता है कांग्रेस की बैठक थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना सीनियर्स से पूछे नियुक्तियां होने का आरोप भी लगाया। कमलनाथ की इन बातों का समर्थन दिग्विजय सिंह ने भी किया। दिग्गी ने मीटिंग में कहा कि अब बिना एजेंडे के बैठकें बुला ली जाती है। बैठक में दिग्विजय सिंह की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब बिना एजेंडे के बैठकें बुला ली जाती हैं। तब उन्हें बताया गया कि वॉट्सऐप पर आपको एजेंडा भेजा गया था। दिग्विजय ने तंज कसते हुए कहा, अध्यक्ष जी 6 बजकर 31 मिनट पर एजेंडा मिला है। अब मैं मोबाइल से मीटिंग में जुड़ा हूं तो एजेंडा कैसे देखूं। मीनाक्षी नटराजन भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात में सुर मिलाती नजर आईं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कांग्रेस की संविधान रैली को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी।

बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस के अंदर मची इस खींचतान को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कमलनाथ दिग्विजय सिंह की नाराजगी पर कहा कि जीतू पटवारी नाथ-दिग्गी गुट को ठिकाने लगाने की तैयारी में हैं। उन्होंने दावा किया कि बैठकों से दूरी, कार्यकर्ताओ की अनदेखी ये सब कांग्रेस धीरे धीरे और बढ़ेगा।

नेताओं की पार्टी में वापसी करानी चाहिए

कमलनाथ ने पार्टी के भीतर मांग उठाई कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले लोगों की घर वापसी कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, अब वे लोग वापस आना चाहते हैं। मुझसे संपर्क कर रहे हैं, हमें उनकी वापसी पर विचार करते हुए कोई फैसला लेना चाहिए।

दूसरे नेताओं ने यह कहा

बैठक में मौजूद दूसरे नेताओं ने कमलनाथ की मांग पर कहा कि जो लोग पार्टी को धोखा देकर गए हैं, उन्हें वहीं रहने दिया जाए, जहां वे हैं। गद्दार लोगों की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि वो लोग हमारे मजबूत लोग रहे हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ है। उनकी वापसी से पार्टी को मजबूत मिलेगी।

इस पर दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने कहा कि अभी इसे होल्ड पर रखते हैं। इस पर बाद में अलग से 10 जनवरी को बात करेंगे।

सम्पादकीय

सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं

चीन के ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी की भारत में दस्तक हो चुकी है। मंगलवार तक ऐसे आठ मामले भारत में भी देखे गए। छोटे बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी बता रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस दुनिया के कई देशों में पहले से ही मौजूद रहा है। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि चीन में फैल रहा वायरस कितना घातक है।

चीन के ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी की भारत में दस्तक हो चुकी है। मंगलवार तक ऐसे आठ मामले भारत में भी देखे गए। छोटे बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी बता रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस दुनिया के कई देशों में पहले से ही मौजूद रहा है। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि चीन में फैल रहा वायरस कितना घातक है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सलाह दी जा रही है कि सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। लोग उसी गाइडलाइन का पालन करें जो कोविड के वक्त 'क्या करें और क्या न करें' के रूप में जारी की गई थी। दरअसल, चीन में एचएमपीवी के मामलों में वृद्धि की खबरों ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ाई है। हालांकि, दुनिया के चिकित्सा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सांसों से जुड़ा सामान्य वायरस है, जो सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां पैदा करता है। खासकर बच्चे व बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन चिंता तब पैदा हो सकती है जब पता चले कि चीन के उत्तरी इलाकों में फैलने वाला वायरस म्यूटेशन से गंभीर बन गया है। हालांकि, चीनी नीति-नियंताओं की दलील रही है कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड के मौसम में सांस की नली का संक्रमण आम बात है। फिर भी बताते हैं कोरोना का स्रोत माने जा रहे चीन में इस वायरस को लेकर गंभीरता देखी जा रही है और उसके नियंत्रण के लिये चीन के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेन्शन संस्थान की देखरेख में विशेष निगरानी सिस्टम बनाया गया है। चीन सरकार ने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में उत्तरी प्रांतों में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के इस वायरस से पीड़ितों की संख्या में वृद्धि के बाद यह कदम उठाया था। हालांकि, एचएमपीवी के स्रोत के बारे में अभी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। दरअसल, यह संक्रामक बीमारी दुनिया के विभिन्न देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। जिसमें खांसी व छींक से निकलने वाले थूक के कणों से यह वायरस फैलता है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिर हाथ मिलाने, दूसरों को छूने व गले मिलने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। यदि हम सावधानी न बरतें तो वायरस हमें संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस से बचाव की ही तरह खांसने -छींकने पर कपड़ा या रूमाल रखने की सलाह दी जाती है। निरंतर कपड़े को बदलने तथा नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने की भी सलाह दी जाती है। जुकाम लगने पर मास्क पहनने तथा घर पर आराम करने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही गुनगुना पानी पीने तथा पौष्टिक आहार की सलाह भी दी जाती है। निश्चित रूप से दमा व सांस की अन्य बीमारियों व दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ितों के लिये यह वायरस कुछ परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति कम ही आएगी। चिकित्सक के परामर्श से ही खांसी- बुखार की दवा लेने की सलाह दी जाती है। बहरहाल, चिकित्सा विशेषज्ञ इस वायरस से भयभीत न होने की सलाह लगातार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस वायरस की खोज इस सदी के पहले ही वर्ष में हुई थी। वायरस का प्रसार चिड़ियाओं के जरिये हुआ था, जो इंसान को संक्रमित कर सकता था। इसकी दशकों से मौजूदगी के चलते लोगों में इसको लेकर एक स्तर तक रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। यह एक सामान्य फ्लू की तरह बताया जा रहा है। हालांकि, इस वायरस के उन्मूलन के लिये कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत कोरोना ने इंसान को पहली बार संक्रमित किया था, कालांतर जिसने महामारी का रूप ले लिया था। वैसे दुनिया में चिंता इस वजह से है कि यह वायरस उसी चीन में फिर सामने आया, जहां से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला था। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन की धरती से ही फैले हैं। भले ही आपको लगता हो कि चीन से फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ थी जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था।

गरीबों को मुंह चिढ़ा रही है नेताओं की बढ़ती सम्पत्ति

देश में भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी के बीच नेताओं की बढ़ती हुई सम्पत्ति में बेशक सीधा कोई संबंध न हो किन्तु सवाल तो उठना लाजिमी है। यक्ष प्रश्न यही है कि करोड़ों की आबादी के पास दो वक्त का खाना नहीं है तो नेताओं की सम्पत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जिनके आर्थिक हैसीयत राजनीति में आने से पहले आम लोगों जैसी थी, किन्तु जनप्रतिनिधि और मंत्री बनते ही उनकी सम्पत्ति में उछाल आ गया। देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं रहेंगी तब तक नेताओं की सम्पत्ति देशहित के दावों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी।

भारत में 12.9 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक तरह से मयस्सर नहीं होता और नेताओं की सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती सम्पत्ति इनकी गरीबी का उपहास उड़ा रही है। इस पर भी तुर्रा यह है कि देश के नेता आम जनता के लिए काम करते हैं। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 332 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास 51 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में किया गया है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपये है। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनआई 2023-2024 के लिए लगभग 1,85,854 रुपये थी, जबकि एक मुख्यमंत्री की औसत स्व-आय 13,64,310 रुपये है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों की इस सम्पत्ति का खुलासा चुनाव आयोग में दिए गए सम्पत्ति के ब्यौरे से हुआ है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो जानकारी दी है, वह सही या कुछ छिपाया गया है। दरअसल देश के नेता चुनाव आयोग को वही जानकारी देते हैं, जिसे वे आयकर रिटर्न में भरते हैं। देश में आयकर रिटर्न भरने वाले भी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंसते रहे हैं। सिर्फ रिटर्न फाइल कर लेने मात्र से किसी की सम्पत्ति या आय दूध की धुली नहीं हो जाती। यदि ऐसा ही होता तो देश के सैकड़ों नेता ईडी, सीबीआई और आयकर के लपेटे में नहीं आते। हालांकि इनके जाल में फंसने के बाद नेता यही राग अलापते रहे हैं कि विपक्ष में होने के कारण उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है। विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्तारुढ भाजपा और उसके सहयोगियों में सभी ईमानदार हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतिश कुमार के समर्थन से बहुमत में केंद्र की भाजपा सरकार में क्या इतना साहस है कि इनके दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई कर सके। क्या यह संभव है कि इन दोनों दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नहीं हो।

यही वजह है कि जांच एजेंसियों पर दुर्भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि जिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, उनके मामले रफा-दफा कर दिए गए। 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95 फीसदी यानी 115 नेता विपक्ष से थे। हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग-अलग राज्यों पर हुई ईडी, सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। वर्ष 2004-14 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें करीब 54 फीसदी यानी 14 नेता विपक्ष से थे। यह संभव है कि मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने सम्पत्ति व्यवसायों के जरिये अर्जित की हो, या फिर पुश्तैनी हो। इसके बावजूद इतनी भारी सम्पत्ति होना देश में गरीबी की जीवन रेखा से नीचे रहने वालों को मुंह तो चिढ़ाती है। जबकि नेता आम लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। वर्ष 2023 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के सभी गरीब लोगों में से एक तिहाई से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं- जो लगभग 12.9 करोड़ लोग हैं। भारत इस संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो अत्यधिक गरीबी में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 डॉलर की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि 3.65 डॉलर निम्न-मध्यम आय श्रेणी में आता है, तथा 6.85 डॉलर उच्च-मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। वैश्विक निर्धारित गरीबी रेखा 3.65 डॉलर प्रति व्यक्ति है।

भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के 40 प्रतिशत के बराबर है, जो 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गई है। भारत में गरीबी दर मिटाने के मामले में केरल सबसे आगे है। केरल में सिर्फ़ 0.71 प्रतिशत आबादी गरीब है। वहीं, बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश में गरीबी दर सबसे ज्यादा है। बिहार में 51.91 प्रतिशत, झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के मुताबिक, भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला। भारत, अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, और बांग्लादेश से भी पीछे है। भारत में भुखमरी की वजह से अक्सर मौत भी हो जाती है। भुखमरी के कारण बच्चों और वयस्कों में कुपोषण, बौनापन, और दुर्बलता हो सकती है। भुखमरी सिर्फ़ भोजन तक सीमित नहीं है, यह सरकार की जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विफलता को दशार्ता है। भारत में भुखमरी की समस्या मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में है। इन राज्यों में से, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल भूखी आबादी का एक तिहाई हिस्सा है।

भारत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसके विभाग को सौ प्रतिशत भ्रष्टाचार से मुक्त कहा जा सकता है। राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकारें हों, हर पार्टी सत्ता में आने के बाद यही दावा करती है कि भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाया जाएगा। सत्ता में आते ही यह वादा हवा हो जाता है। जब कभी कोई भ्रष्ट कार्मिक पकड़ा जाता है, तब सरकार यही दावा करती है कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, किन्तु यह दावा कभी नहीं करती कि जिस विभाग का आरोपी पकड़ा गया है, वह विभाग अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है।

देश में भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी के बीच नेताओं की बढ़ती हुई सम्पत्ति में बेशक सीधा कोई संबंध न हो किन्तु सवाल तो उठना लाजिमी है। यक्ष प्रश्न यही है कि करोड़ों की आबादी के पास दो वक्त का खाना नहीं है तो नेताओं की सम्पत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जिनके आर्थिक हैसीयत राजनीति में आने से पहले आम लोगों जैसी थी, किन्तु जनप्रतिनिधि और मंत्री बनते ही उनकी सम्पत्ति में उछाल आ गया। देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं रहेंगी तब तक नेताओं की सम्पत्ति देशहित के दावों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी।

अपने ही सांसदों का विश्वास खो बैठे थे ट्रूडो

जस्टिन ट्रूडो के अच्छे दिन जाने वाले हैं। लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उनकी कुर्सी संभालने वाले का नाम फाइनल होने तक वे पद पर बने रहेंगे। बुधवार को राष्ट्रीय कॉकस की बैठक से पहले उन्होंने अपनी बची-खुची इज्जत बचा ली। ट्रूडो एक विफल प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। उनकी वजह से लिबरल पार्टी को चुनाव में मतदाताओं के बीच उतरना मुश्किल साबित हो रहा है। अब उस चेहरे की तलाश है, जिसे आगे कर आम चुनाव लड़ा जाये।

ट्रूडो ने वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक से चर्चा की, कि क्या वह अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार होंगे? डोमिनिक लेब्लांक की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो इस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। लिबरल पार्टी को नेतृत्व देने के वास्ते जो संभावित दावेदार हैं, उनमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड को भी आगे किया जा रहा है। पूर्व आवास मंत्री सीन फ्रेजर, विदेश मंत्री मेलानी जोली, नवाचार मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन, परिवहन मंत्री अनीता आनंद, पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी, और पूर्व बी.सी. प्रीमियर क्रिस्टी क्लार्क जैसे नाम भी सामने आने लगे हैं। कनाडा की सत्ता के गलियारे में भूचाल की वजह सर्वेक्षण भी रहे हैं। पिछले एक साल के सर्वेक्षणों से पता चला है, कन्जर्वेटिव्स को सत्तारूढ़ लिबरल्स के मुकाबले दोहरे अंकों की बढ़त हासिल है। गुजरे शुक्रवार को जारी ह्यएंगस रीड सर्वेक्षणह्न से पता चलता है, कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में, लिबरल पार्टी को केवल 13 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होना है, लेकिन यदि कोई नया नेता आता है, तो यह संख्या बदल भी सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं सुश्री फ्रीलैंड यदि सत्ता संभालती हैं, तो 21 प्रतिशत मतदाता लिबरल पार्टी के लिए मतदान करेंगे, जो सर्वे के जरिये खंगाले गए लीड उम्मीदवारों में सबसे अधिक संख्या है। ह्यएंगस रीडह्न ने 27 दिसंबर से मंगलवार 31 दिसम्बर, 2024 तक, 2,406 कनाडाई वयस्कों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण किया, जो एंगस रीड फोरम के सदस्य हैं। इसके परिणाम के हवाले से क्रिस्टिया फ्रीलैंड को फ्रंट रनर समझा जा रहा है।

कनाडा में संसदीय चुनाव 20 अक्तूबर, 2025 को निर्धारित है। लेकिन, ट्रूडो की सत्ता में सहयोगी रही एनडीपी के समर्थन वापस लेने का मतलब है कि चुनाव शायद बहुत पहले हो जाएं। यदि, चुनाव पहले कराना है, तो संसद की अनुमति चाहिए। कई लिबरल सांसद वित्त मंत्री के रूप में क्रिस्टिया फ्रीलैंड के प्रदर्शन से नाखुश थे, और उन्हें बदलने की वकालत कर रहे थे। क्रिस्टिया के इस्तीफे के बाद, बंदूकें ट्रूडो के विरुद्ध तन गईं। पिछले कुछ हफ्तों में क्षेत्रीय कॉकस की बैठकों, और लिबरल सांसदों की प्रतिक्रियाओं को देखकर लगने लगा है, कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के पास अब टीम नहीं है। ट्रूडो यह कहने की हालत में नहीं हैं, कि उनकी छवि खराब करने में भारत और चीन ने साजिश रची है।

कनाडा की संसद में दो सदन हैं। निचला सदन, ह्यहाउस ऑफ कॉमन्सह्न में 338 सदस्य हैं, जो एकल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम चार वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। दूसरा है सीनेट, जिसके 105 सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संसद में आम तौर पर कई पार्टियों का प्रतिनिधित्व दिखता है, लेकिन कनाडा में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, लिबरल और कंजर्वेटिव का दबदबा बना रहता है।

ट्रूडो के बुरे दिन अक्टूबर, 2024 से शुरू हुए, जब उन्हीं की पार्टी के दो दर्जन सांसदों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। क्रिसमस आते-आते पार्टी के अंदर विप्लवी सांसदों की संख्या 70 से ऊपर पहुंच गई। यह संकट और गहराया, जब क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वित्त मंत्री, और उप प्रधानमंत्री के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उस दिन पद छोड़ा, जिस दिन उन्हें अपना आर्थिक और राजकोषीय अपडेट देना था। जीएसटी अवकाश और 250 डॉलर की छूट जैसे खर्च के हथकंडों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, और संभावित ट्रम्प टैरिफ से निपटने में गंभीरता की कमी का हवाला दिया। इस काण्ड के बाद से अटलांटिक, ओंटारियो, और क्यूबेक कॉकस ने संकेत दिया है, कि उनके अधिकांश सदस्य अब ट्रूडो के शीर्ष पर बने रहने का समर्थन नहीं करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो की पार्टी लिबरल्स के पास 153 सीटें हैं, जिनमें से 131 सीटें इन तीन क्षेत्रों में हैं।

कनाडा की पॉलिटिकल कहानी का दूसरा पहलू है, भारतीय मूल के वोटर। कनाडा के सिखों का राजनीतिक दबदबा असाधारण है, क्योंकि वे ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में लगभग दो दर्जन संघीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी गहरी और रणनीतिक भागीदारी है। हालांकि, कनाडा की हिंदू आबादी आठ लाख की संख्या वाले सिख समुदाय से थोड़ी बड़ी है, लेकिन यह भौगोलिक रूप से कम केंद्रित, या अपने राजनीतिक विचारों में एकजुट नहीं है।

ट्रूडो के हर कदम का लक्ष्य, सिख मतदाताओं को अपने आईने में उतारने का रहा है। उनकी मेहनत तब और बढ़ गई है, जब खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बने हैं। शुक्रवार को न्यू डेमोक्रेट्स जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, इससे ट्रूडो का कार्यकाल और भी संदेहास्पद हो गया। कनाडा के निचले सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 सिख सांसद हैं। नवीनतम फेरबदल के बाद ट्रूडो के मंत्रिमंडल में स्वयं सहित 39 मंत्री हैं। ट्रूडो ने 2016 में यह दावा कर दिया था, कि उनके मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट से ज्यादा सिख हैं। 2018 में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी को आधिकारिक स्वागत समारोह में आमंत्रित कर उन्होंने दिल्ली से सम्बन्ध खराब करने की शुरूआत कर दी थी। ट्रूडो ने बार-बार नई दिल्ली के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखने से ज्यादा सिख मतदाताओं को लुभाने को प्राथमिकता दी। वर्ष 2018 में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री राल्फ गुडले ने आतंकवाद से संभावित खतरे वाली रिपोर्ट में सिख चरमपंथ की चर्चा कर दी थी। खालिस्तान समर्थकों ने जब धमकी दी, तो 2019 में उस सन्दर्भ को राल्फ गुडले ने हटा दिया। वर्ष 2020 में, मोदी सरकार ने कनाडा पर भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, जब ट्रूडो ने पीएम मोदी के कृषि सुधारों का विरोध कर रहे सिख किसानों के समर्थन में बात की थी। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या साजिश में गृहमंत्री अमित शाह का नाम उछालकर ट्रूडो ने भारत-कनाडा संबंधों में और कड़वाहट घोल दी।

पीथमपुर में पूरी तरह निरापद होगी कचरा निपटान की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर भेजने का फैसला यद्यपि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर किया था, परन्तु जब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए उस पर विधिवत अमल की कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय जनता के द्वारा किए जा रहे उग्र विरोध ने सरकार के लिए असमंजस की स्थिति निर्मित कर दी है। यहां यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर से कचरा उठवाकर उसे पीथमपुर भेजने का काम राज्य सरकार केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर कर रही है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी थी। परन्तु पीतमपुर में कुछ दिनों से जिस तरह विरोध का वातावरण बना हुआ है उसे सौहार्द्रपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पहला की है उसके लिए वे साधुवाद के हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पीतमपुर की जनता के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित की है, वह निश्चित रूप से पीथमपुर की स्थानीय आबादी को यह विश्वास दिलाने में कारगर साबित हो सकती है कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन की प्रक्रिया पूरी तरह निरापद होगी। गौरतलब है कि पीथमपुर में सभी वर्गों के लोगों ने जिस तरह एकजुट होकर अपना विरोध जताया। उसकी पल-पल की जानकारी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ले रहे थे और उन्होंने अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं इंदौर के प्रभावशाली विधायक कैलाश विजयवर्गीय को स्थानीय जनता को समझा-बुझाकर कर उनके आक्रोश को शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी, परंतु जब उन्हें भी इस काम में पर्याप्त सफलता नहीं मिली तो आनन-फानन में मुख्यमंत्री ने भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक आमंत्रित की जिसमें उपमुख्यमंत्री द्वय राकेश शुक्ला, जगदीश देवड़ा, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय , मुख्य सचिव अनुराग जैन, वरिष्ठ विधिवेत्ता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ इस विषय में गहन मंत्रणा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार दृढ़ता पूर्वक जनता के साथ खड़ी है और उसकी सुरक्षा के प्रति पूरी सचेत हैं।

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर से पीथमपुर तक कचरे का परिवहन माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप सुरक्षा मापदंडों का पूरी रह परिपालन करते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि जनता के मन में यदि कोई खतरे या डर का भाव आया तो सरकार इस विषय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी और इस मामले में माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा उसके पालन के लिए हम तत्पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि सरकार को पीथमपुर के लोगों के हितों का पूरा ध्यान है। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चालीस साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में ही भोपाल में यह भयावह त्रासदी हुई थी। कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और अब वह माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सरकार द्वारा सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखकर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के लिए पीथमपुर के चयन और जनस्वास्थ्य पर उसके कथित हानिकारक प्रभावों को लेकर जो गंभीर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उनसे मुख्य सचिव अनुराग जैन असहमति जताते हुए कहा है कि हर राज्य में एक हैजर्डस् वेस्ट डिस्पोजल फेसिलिटी है। मध्यप्रदेश में यह पीथमपुर में है। 2013 और 2015 में भी पीथमपुर में इसी तरह का कचरा जलाया जा चुका है, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। मुख्य सचिव ने कचरे के निष्पादन से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के खतरे की आशंका निर्मूल बताते हुए कहा कि यह आशंका पूरी तरह शून्य है। गत दिवस भोपाल में मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले से जुड़े हर सवाल का जिस तरह सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया वह पीथमपुर में आंदोलन कर रहे लोगों की सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। अनुराग जैन ने कहा कि पूरा कचरा इसी ठंड के मौसम में ही जलाया जाएगा बल्कि यह कचरा हर मौसम में जलाया जाएगा और वातावरण पर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। यदि किसी मौसम में कचरा जलाने के बाद अध्ययन में वातावरण में हानिकारक तत्वों की अधिकता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया बदली जाएगी।

नारायणपुर ग्राम कोकोड़ी में स्थापित किया गया नवीन पुलिस सहायता केन्द्र

पुलिस सहायता केन्द्र खुलने से ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर

गणेश वैष्णव । सिटी चीफ
नारायणपुर, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल मुक्त सशक्त बस्तर की कल्पना को साकार रूप देने हेतु क्षेत्र में लगातार सघन नक्सल विरोधी ''माड़ बचाव'' अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला नारायणपुर अन्तर्गत थाना बेनूर के ग्राम कोकोड़ी में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के निदान एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 06.01.2025 को ''पुलिस सहायता केन्द्र'' खोला गया है। थाना बेनूर से ग्राम कोकोड़ी की दूरी लगभग 14 है। कोकोड़ी एवं आसपास के ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के निदान हेतु अब थाना बेनूर जाने की आवश्यकता नही पड़ेगी। ग्रामीण सीधे अपनी समस्यायें पुलिस सहायता केन्द्र कोकोड़ी में बता सकते हैं। थाना बेनूर से ग्राम कोकोड़ी की दूरी अधिक होने से सड़क दुर्घटना होने पर बेनूर पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लगता था। पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित होने से आसपास में किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस सहायता केन्द्र से तत्काल पुलिस घटना स्थल पहुंचकर घायलों एवं पीड़ितों की सहायता करेगी। ग्राम कोकोड़ी में पुलिस सहायता केन्द्र खुलने से ग्राम कोकोड़ी एवं आसपास के गांव में निवासरत् ग्रामीणों में अत्यंत खुशी का माहौल है।

न्यायिक अधिकारियों के द्वारा उप-जेल का किया निरीक्षण

पट्टा पेश एवं सक्षम जमानतदार को जानकारी दी

गणेश वैष्णव । सिटी चीफ
नारायणपुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री उत्तरा कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा मरकाम एवं व्यवहार न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय कोण्डागांव के द्वारा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के कामकाज को मजबूत करने के उद्देश्य में उप-जेल नारायणपुर का किया दौरा। इस दौरान विचाराधीन बंदी जिनका जमानत हो गया है फिर भी वह जेल में निरूद्ध ऐसे बंदियो को चिन्हांकित कर उन्हे पट्टा पेश एवं सक्षम जमानतदार की जानकारी दी गई साथ ही जिन बंदियों को जमानत का आवेदन लंबित है तथा निराकृत नहीं हुई है या जमानत का आवेदन लगाना चाहते है उन्हें जमानत का आवेदन लगाने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही बंदियों के प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं हुए हैं उन बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के माध्यम से लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं नियुक्त करने के संबंध में बताया गया तथा सहायक जेल-अधीक्षक को नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्त के लिए आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में जाति भेदभाव छुआ-छूत के संबंध पूछा गया तो बंदियों के द्वारा ऐसे नहीं होने की जानकारी दी गई। तथा समस्त बंदियों का खान पान व उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया गया। इस अवसर पर सहायक जेल-अधीक्षक संजय कुमार नायक, प्रतिधारक अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश कश्यप, घासीराम नेताम, पारेश्वर देवांगन, रविन्द्र बघेल अधिकार मित्र उपस्थित थे।

06 जनवरी को बीजापुर में नक्सलियों किये गये IED ब्लास्ट में हमारे 8 जांबाज जवान व एक वाहन चालक शहीद हो गये

गणेश वैष्णव । सिटी चीफ
नक्सलियों का कायराना करतूत फिर एक बार सामने आया है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता आक्रोशित है। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों,पत्रकार बंधुओं गणमान्य नागरिक,बुद्धिजीवियोंसे अनुरोध है की, देश को हुई इस अपूर्णीय क्षति हेतु आहूत प्रार्थना सभा मे सम्मिलित होकर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिनांक *07.01.2025, दिन- मंगलवार* समय - *शाम 6.30 बजे स्थान- जय स्तभ चौक जिला नारायणपुर में किया जायेगा। किसी ने अपना पिता, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना दोस्त तो किसी ने अपना संबंधी खोया है, इस दु:ख की घड़ी में हमे एकजुट होकर परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए। वीरगति को प्राप्त हमारे सभी जवानों को शत शत नमन।

नए वर्ष में भव्य स्वागत किया अजय सिंह राहुल भैया का बृजेश गर्ग सोनू मित्र मंडली ने

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ
सतना, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री चुरहट विधायक श्री अजय सिंह राहुल भैया का सतना के साई पैलेस में नव वर्ष मिलन समारोह के दौरान कोठी के कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया, कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता एवं सतना लोकसभा के प्रभारी बृजेश गर्ग सोनू कोठी की कोठी क्षेत्र की मित्र मंडली ने उनके साथ सतना में आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल भैया का भव्य आत्मीय स्वागत किया फूल माला बुके के साथ अजगर माला पहनकर नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी इस दौरान परिसर अजय सिंह राहुल भैया जिंदाबाद के जयकारे से गूंज गया , प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान अभय सिंह रोली भैया जिला कांग्रेस कमेटी के मुखिया दिलीप मिश्रा रेगांव विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद के साथ-साथ जिला कांग्रेस कमेटी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी की मौजूदगी में,बृजेश गर्ग सोनू कोठी की मित्र मंडली के प्रमुख साथी एवं प्रमुख सहयोगी अरुण सिंह गहरवार, उमेश सिंह पप्पू, विजय राज सिंह, पंडित जगन्नाथ शर्मा, आदित्य सिंह,बद्री सिंह, केशव सिंह, हरिहर मूर्ति त्रिवेदी, तिलक राज सिंह, कृष्ण भान सिंह, मनिंदर सिंह जीतू उमेश

डोहर, उमाशंकर पांडे,सुखेंद्र सिंह, सूरज सिंह, कीर्ति प्रसाद गर्ग, रज्जू आदिवासी, लल्ली कुशवाहा, जुगराज कुशवाहा श्री राम कुशवाहा ,कुवर बहादुर सिंह, राजेश कुशवाहा ,गुड्डू त्रिपाठी, विजय सिंह, प्रेम बहादुर सिंह, रामदयाल प्रजापति, राजभान कोरी, विनोद प्रजापति, गणपत आदिवासी, विवेक आदिवासी सहित कई अन्य साथी मित्र जनो ने राहुल भैया का स्वागत किया।

तुलसी महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई प्रदेश सचिव सचिन पटेल ने खोला मोर्चा

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ
अनूपपुर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रदेश सचिव सचिन पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में व्याप्त अनियमितता को लेकर दिनांक 7 जनवरी 2024 को महाविद्यालय प्रांगण में उग्र धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाना था जिसको लेकर अनूपपुर तहसीलदार कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल महाविद्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन लिया। प्रदेश सचिव सचिन पटेल ने अपने प्रस्तुत ज्ञापन में लेख करते हुए महाविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्राचार्य द्वारा शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में हो रहे निर्माण कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। महाविद्यालय में अध्यनरत बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष के अधिकांश छात्राओं की अंक सूची त्रुटि विदेल्ड पाया गया है जिसे जल्द से जल्द सुधार कराया जाए। महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा सिर्फ कागजों तक सीमित है कभी भी कैंटीन नहीं खुलता है और कैंटीन संचालक कौन है इसकी भी जानकारी नहीं पता है संचालक महाविद्यालय में कैंटीन का किराया भी नहीं जमा करते हैं महाविद्यालय में छात्राओं की बस की सुविधा सिर्फ कागजों तक सीमित है धरातल में कुछ नहीं है महाविद्यालय में कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित नहीं है। महाविद्यालय में आज दिनांक तक डिजिटल आईडी कार्ड भी वितरण नहीं किया गया है महाविद्यालय में हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है महाविद्यालय में गणित विषय का कोई प्रोफेसर नहीं है जिसके लिए पूर्व में भी प्राचार्य को अवगत कराया गया था किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेलकूद कलैंडर का सूचना पूर्व से छात्राओं को नहीं दी जाती है जिससे कि महाविद्यालय में अध्यनरत नियमित छात्राएं उक्त गतिविधियों की पूर्व से जानकारी के अभाव में खेलकूद में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। जिसका मुख्य कारण यह है कि क्रीड़ा प्रभारी एवं प्राध्यापक अपने कुछ गिने चुने या चहेते को सभी खेल के गतिविधियों में ले जाया जाता है और महाविद्यालय में अलग-अलग खेलों के लिए महाविद्यालय से फर्जी राशि का आहरण किया जा रहा है। इस तरह महाविद्यालय में व्याप्त विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर के एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सचिन पटेल ने मोर्चा खोल दिया है और इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष आदित्य राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष लालजी पटेल ,कॉलेज अध्यक्ष राहुल वर्मा, सीमा सिंह, प्रीति सिंह, अजय चौधरी, हीरामणि परस्ते, सतीश महोबे, नागेंद्र सेन, प्रिया सिंह, रिंकी राठौर, तेजस्वी यादव, राहुल वर्मा, अखिलेश सिंह, अभिषेक तिवारी सहित संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता व छात्र-छात्राएं भारी संख्या में उपस्थित रहे।

शासन से प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले की एडवाईजरी हुई जारी

आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ के आयोजन में महाकुम्भ मेला परिक्षेत्र में भगदड, अग्निकांड, डूबना, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या इत्यादि के निस्तारण तथा महाकुम्भ 2025 को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सहारनपुर एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा महाकुम्भ-2025 में जाने वाले तीर्थयात्री एवं आमजन के लिए एडवाईजरी जारी की गयी है। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि महाकुम्भ मेला 2025 मोबाईल एप डाउनलोड करें और मेले की जानकारी प्राप्त करें। यात्रा से पूर्व निवास स्थान सुनिश्चित करें। बदलते मौसम के अनुसार कपड़े एवं खान-पान का सामान साथ रखें। गर्म एवं ऊनी वस्त्र साथ में रखें। मौसम की पूर्व जानकारी हेतु मौसम विभाग की आईएमडी की वेबसाइट देखें। आपदा की पूर्व चेतावनी हेतु सचेत मोबाईल एप डाउनलोड कर चेक करें। 60 वर्ष से अधिक आयु या पूर्व से बीमार व्यक्ति यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य करायें। चिकित्सक से सलाह लेने के उपरान्त ही महाकुम्भ मेले में जाये। हृदय रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रोगी यात्रा के समय विशेष सावधानी बरतें एवं अपनी दवा निरंतर समय पर लें। यदि आयुष्मान कार्डधारक है तो कार्ड साथ रखें जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में सरकारी एवं निजी चिकित्सालय में मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि संगम क्षेत्र पंहुचने हेतु पैदल चलना पड सकता है इसलिए शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए पानी या ओआरएस का घोल पीते रहें। मेला क्षेत्र में अत्याधिक भीड की संभावना होने के दृष्टिगत गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। बच्चों, वृद्धजनों व गर्भवती महिलाओं को अकेले स्नान ना करने दें तथा गहरे पानी में जाने से बचे। चप्पल जूते का प्रयोग करें एवं कीचड वाले स्थान पर ना चलें। सिर दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, दिल की धडकन का तेज होना, उल्टी आना, हाथ-पांव व होठों का नीला पडना, थकान होना, सांस फूलना, खांसी होना अथवा अन्य लक्षण होने पर मेले में स्थापित निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से तत्काल सम्पर्क करें। खाने से पहले और शौचालय उपयोग के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोयें। धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। मच्छरों से बचाव रखें।
सरकारी नल, वाटर एटीएम के पानी का उपयोग करें एवं खाने-पीने हेतु उबालने के बाद ही प्रयोग करें। सब्जी फल इत्यादि को अच्छे से धो कर ही सेवन करें। गरम कपडे, कम्बल, रजाई पर्याप्त मात्रा में रखे। हीटर, अलाव इत्यादि का प्रयोग टेंट के अन्दर ना करें, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। कुम्भ मेले में आपात स्थिति में महाकुम्भ हेल्पलाईन-1920, पुलिस हैल्प लाईन-112 व आपदा हैल्प लाईन-1077 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सहारनपुर में कारोबारी की हत्या

शव मकान में कमरे के अंदर मिला, पुलिस जांच में जुटी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ *सहारनपुर, सहारनपुर जनपद में मोहल्ला गाडो के चौक में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। उनका शव मकान में कमरे के अंदर अर्धनग्न हालत में मिला है। जानकारी के अनुसार कारोबारी सेवाराम धारिया जेवर गिरवी रखकर ब्याज पर रुपये देने का काम करते थे। वह गाडो का चौक मोहल्ला में रहते थे। जबकि उनका बेटा पुरानी मंडी क्षेत्र में दूसरे मकान में रहता है। कारोबारी सेवाराम धारिया (64) की हत्या कर दी गई है। उनका शव मकान में कमरे के अंदर अर्धनग्न हालत में मिला है। उनके हाथ-पैर बंधे हुए है और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। कारोबारी सेवाराम धारिया जेवरात आदि गिरवी रखकर ब्याज पर रुपये देने का काम करते थे। वह गाडो का चौक मोहल्ला स्थित मकान में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटा प्रणव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पुरानी मंडी क्षेत्र में दूसरे मकान में रहता है। सेवाराम धारिया रोजाना शाम के समय बेटे के पास मकान पर खाना खाने के लिए जाते थे। बीती शाम वह खाना खाने नहीं आए। उनका मोबाइल भी बंद मिला। परिवार के सदस्यों को लगा कि किसी काम में व्यस्त होंगे। लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचे तो बेटा तलाश करते हुए मकान पर पहुंचा। मकान का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर कमरे में सेवाराम का शव अर्धनग्न हालत में पड़ा था। सूचना मिलने पर मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस के अनुसार जिस तरीके से हाथ-पैर बांधे गए हैं और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है, उससे लग रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। कमरे की अलमारी का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। लूट के एंगल से भी जांच की जा रही है। शव एक दिन पुराना लग रहा है। पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। मकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।*

पद्मश्री बाबा योगेंद्र की 101 वीं जयंती पर हुई विचार गोष्ठी

विभाग संयोजक लोकेश वत्स ने पद्म श्री बाबा योगेंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला प्रकाश

गौरव सिंघल। सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, संस्कार भारती (कला एवं साहित्य जगत के अखिल भारतीय संगठन) के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी की 101 वीं जयंती पर आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन संत नगर देवबंद में किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सहारनपुर विभाग संयोजक डॉ0 लोकेश वत्स रहे। अध्यक्षता जिला संरक्षक एस सी शर्मा ने की। संचालन महामंत्री स्तुति शर्मा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत भारत माता और पद्म श्री बाबा योगेंद्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य वक्ता विभाग संयोजक लोकेश वत्स ने पद्म श्री बाबा योगेंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कहा कि उनका त्याग और सादगी पूर्ण जीवन आदर्श अपनाने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत है। सूदूरवर्ती क्षेत्रों में कलाकारों को खोजना और उन्हें मंच प्रदान करना मुख्य ध्येय था। इसी को संस्कार भारती के जरिए उन्होंने आगे बढ़ाया। संस्कार भारती के संस्थापक अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में उनका अतुलनीय योगदान रहा।
हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर कलाहित समझित में कार्य करना चाहिए।
जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा बाबा योगेंद्र जी कला जगत के लिए पूरे जीवन समर्पित रहे। आज कलाकारों व कला के उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय है।
महासचिव स्तुति शर्मा, पुरनचंद , नरेंद्र कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर मुख्य रूप से विजेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, पंडित अखिलेश शर्मा, नितिन कुमार, कौशिकी शर्मा आदि उपस्थित रहे।

सहारनपुर प्राकृतिक खेती, गुणवत्तापरक उत्पाद और

जायकेदार गुड़, खाण्ड, शक्कर के निर्यात का प्रमुख केंद्र बना

सुरेंद्र सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर। खेती प्रधान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद प्राकृतिक एवं आर्गेनिक खेती और उसके गुणवत्तापरक उत्पादों एवं जायकेदार एवं स्वास्थ्यवर्धक गुड़, शक्कर और खांड के निर्यात का प्रमुख केंद्र बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं नाबार्ड बैंक और स्थानीय प्रशासन के भरपूर प्रोत्साहन से जिले में प्राकृतिक, आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। सहारनपुर के प्रगतिशील किसान पद्मश्री सेठपाल चौधरी ने बताया कि शिक्षित युवा ही नहीं बल्कि युवतियां और महिलाओं का इस नए रूझान को लेकर जुनून देखते ही बनता है। सहारनपुर से बड़े पैमाने पर जायकेदार और स्वास्थ्यवर्धक खांड, गुड़ एवं शक्कर की यूरोप, आस्ट्रेलिया, जापान, खाड़ी के देशों दुबई, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस में निर्यात हो रहा है। भारत को विदेशी मुद्रा मिल रही है और यहां के किसानों में संपन्नता आ रही है। बहुत से किसान खेती के साथ-साथ उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री खुद ही कर रहे हैं। सहारनपुर मंडल के गन्ना उपायुक्त ओमप्रकाश सिंह के मुताबिक सहारनपुर मंडल में 40 से 50 किसान प्राकृतिक और उससे कहीं ज्यादा संख्या में आर्गेनिक गन्ने की खेती कर रहे हैं। कोई भी किसान घाटे में नहीं है। सहारनपुर की शिवालिक पर्वत मालाओं में स्थित मां शाकुम्बरी देवी से पांच किलोमीटर दूर कोटड़ी बहलोलपुर गांव के प्रगतिशील किसान संजय चौहान, उनकी पत्नी ममता चौहान और बीटेक 22 वर्षीय बिटिया यशस्वी चौहान और सहारनपुर के मुन्ना लाल गल्स डिग्री कालेज की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा शुभावरी अपनी ढाई सौ एकड़ जमीन पर गाय आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। शुभावरी ने बताया कि उनके यहां कई एकड़ में गन्ने की प्राकृतिक खेती होती है और उनका परिवार आर्गेनिक गुड़-शक्कर बनाता है। भारत में शक्कर का दाम साधारण 100 रूपए किलोग्राम

और गुड़ का 120 रूपए किलोग्राम एवं सूखे मेवे वाले गुड़-शक्कर का भाव 550 रूपए किलोग्राम तक है। पूरा कारोबार आन लाइन है। उनके यहां देशी नस्ल की गिर एवं साहीवाल गाएं हैं जिनके घी की सबसे ज्यादा मांग पेरिस-फ्रांस में है। उनका गुड-शक्कर दुबई और खाड़ी देशों में भी जाता है। वह अभी सरकार से किसी तरह की सहायता नहीं ले रहे हैं। शुभावरी चौहान ने बताया कि उनके यहां तैयार गुड़, शक्कर और फलों की नए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सराहना की और हर तरह की शासकीय सहायता एवं सहयोग का भरोसा दिया है। जिला गन्नाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि जिले में प्राकृतिक खेती और उत्पादों को तैयार करने के लिए एफपीओ नामक गैर सरकारी संगठन के तहत करीब दो हजार किसान प्राकृतिक और आर्गेनिक खेती से जुड़े हैं। उनको नाबार्ड बैंक के जरिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अनेक किसान आधुनिक संयंत्रों के जरिए हाईजैनिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी संजय सैनी ने बताया कि वह प्रदूषण मुक्त संयंत्र लाए हैं जो खांड की नमी को 15-16 फीसद से घटाकर 6 फीसद कर देता है जिससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। उनके उत्पाद भी विदेशों में जा रहे हैं और ऊंचे दाम मिल रहे हैं। यहां के बहुत से किसान जापानी तकनीक पर आधारित संयंत्रों एवं मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईजैनिक संयंत्रों से बनी शक्कर का दाम 130 रूपए, गुड़ का 120 और खांड का 180 रूपए किलोग्राम है। संजय सैनी का कहना है कि पहले समय में खांड की सुखाई पैरों से की जाती थी जिस कारण लोगों ने इसका इस्तेमाल और उत्पादों को लेना बंद कर दिया। अब आधुनिक तरीकों से खांड, शक्कर सुखाने से उनकी शुद्धता, गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसी कारण उनकी निर्माण लागत बढ़ती है। ऐसे ही लाभपरक मूल्य मिलने से किसान और कारोबारी को भारी मुनाफा हो रहा है।

ददिया पोटियापाट शांतिधाम में दीवार निर्माण कार्य को क्षती पहुंचाने का बम्हनी सरपंच पर लगा आरोप

ददिया सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बम्हनी सरपंच की शिकायत कर कि कार्यवाही कि मांग

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ

लालबर्रा, नगर मुख्यालय अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ददिया में पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में करवायें गये निर्माण कार्य को क्षती पहुंचाने व पोटिया पाट का पुन: सीमांकन करवाने को लेकर ददिया सरपंच श्रीमती रिषी पंछी राजेन्द्र भलावी व जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनीराम भोयर ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पहुंचकर जनपद पंचायत सीईओ,तहसीलदार लालबर्रा व थाना प्रभारी से बम्हनी सरपंच बी आर ढबाले कि लिखीत शिकायत 21/12/2024 व 23/12/2024 को कि गई है।

वहीं हम आपको अवगत करा देवें कि बम्हनी सरपंच आये दिन विवादों में रहते हुए अखबारों कि सुर्खियों में रहते हैं तथा ददिया सरपंच के द्वारा पुर्व में भी बम्हनी सरपंच कि लिखीत शिकायत निर्माण कार्य को तुड़वाने व पोटिया पाट का सीमांकन को लेकर शिकायत कि गई थी और बकायदा हल्का पटवारी व राजस्व अमले के द्वारा मौके स्थल पर पहुंचर सीमांकन भी किया गया था लेकिन ददिया सरपंच व ग्रामीण जन सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे वहीं ददिया सरपंच व ग्रामीणों का आरोप था कि पटवारी ने हमारी बातों को नजर अंदाज कर सीमांकन किया है।

वहीं शिकायत पत्र में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत ददिया के द्वारा 2015-16 में वैनगंगा पोटियापाट पर शांतिधाम के नाम से मनरेगा कार्य स्वीकृत हुआ था जिसकी लागत 4 लाख 99 हजार रुपए थी,

जिसका टीएस नंबर 2060051 है ग्राम पंचायत ददिया द्वारा शांति धाम निर्माण कार्य के अलावा पानी के एवं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक दीवार लगभग 30 मीटर बनाई गई थी, जिसे ग्राम पंचायत बम्हनी सरपंच बी आर ढबाले द्वारा ग्राम पंचायत ददिया सरपंच व ग्रामीणों कि बिना अनुमति से तोड़कर गहरा गड्ढा बना दिया गया है यह कार्य हमारे ग्राम पंचायत की धरोहर थी पानी मिट्टी के कटाव को रोकने वाले निर्माण कार्य को तोड़ने को लेकर लिखीत शिकायत कि गई है वहीं तहसीलदार महोदय को भी पुन: सीमांकन करवाने हेतु शिकायत कि गई है।

शिकायत कर कि गई कार्यवाही कि मांग वहीं शिकायत कर कार्यवाही कि मांग करने वालों में प्रमुख रूप से श्रीमती रिषी पंछी भलावी सरपंच ददिया, मनीराम भोयर जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि,कृष्ण कुमार मोहबे पुर्व सरपंच, तुलसीराम बोपचे पुर्व जनपद पंचायत सदस्य, ज्ञानचंद मात्रे पुर्व सरपंच, राजेन्द्र भलावी, प्रमोद हरिनखेडे, विरेन्द्र बोपचे, नरेंद्र भोयर, प्रेमलाल रहांगडाले, राधेश्याम कड़ोकर,सौरभ लांजेवार, रमेश राणा,मन्नु लाल बोपचे, गणेश आस्वाले, मिथलेश ठाकरे, दिनेश बिसेन,खिलेन्द्र मोहबे,गनीराम भोयर,किशन हरिनखेड़े,मिलेन्द्र मोहबे, संजय मेरावी,मानिकराम बोपचे, कमलेश राउत, पन्नालाल जी ठाकरे, हरिराम लांजेवार, रामचंद्र राजुरकर,विजय नारबोदे, सहित अन्य और भी लोगों ने शिकायत कर कार्यवाही कि मांग कि है।

4 माह बीतने के बाद भी नहीं हुई किसान के आवेदन पर कोई कार्यवाही

नर्मदा ट्रैक्टर एजेंसी ने धोखाधडी से पहले महंगा बेचा ट्रैक्टर फिर अवैध राशि वसूल करने दबंगई से किया ट्रैक्टर जप्त

यशपाल सिंह जाट। सिटी चीफ

अनुपपुर, अनुपपुर अनुपपुर जिले के ग्राम झिरिया टोला थाना रामनगर निवासी रितेश तिवारी ने लगभग एक माह पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रितेश तिवारी ने 23 जून 2023 को 8 लाख 45 हजार रुपए में ट्रैक्टर एवं ट्राली नर्मदा मोटर्स की कोतमा शाखा से क्रय किया जिसमें ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा 60 हजार रुपए की छूट प्रदान की गई जिससे रितेश तिवारी को बची हुई शेष राशि 7 लाख 85हजार रुपए ट्रैक्टर एजेंसी को देना थी जिसमें रितेश तिवारी द्वारा निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया 41 हजार , की राशि दो किस्तों में एजेंसी के कर्मचारी मुक्कू तिवारी एवं नारद को दिए इसके बाद 25,मार्च 2024 को एजेंसी मालिक राजीव शुक्ला एव मुक्कू तिवारी को अपने निवास झिरिया टोला में 2 लाख 9 हजार रुपए दिए गए एवं एक दो दिनों बाद ही 35हजार

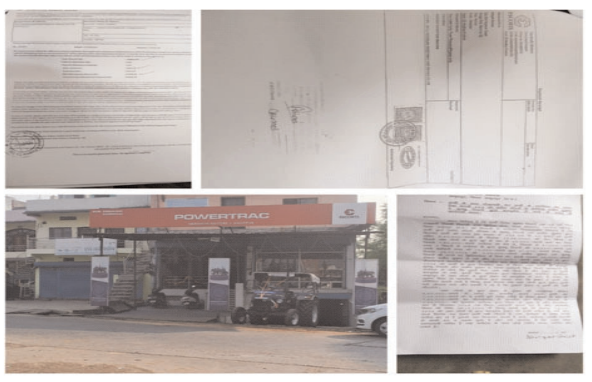

रुपए राजीव शुक्ला जी द्वारा घर आकर ले जाया गया , इसके बाद चोला मंडलम अनुपपुर से 5 लाख 17 हजार रुपए एजेंसी द्वारा फाइनेंस करवा दिया गया ऐसे ट्रैक्टर एजेंसी के पास तय की गई राशि से 17 हजार रुपए अधिक जमा हो गई इसके बाद चोला मंडलम अनुपपुर की ई एम आई किस्त की राशि रितेश तिवारी द्वारा नियमित रूप से जमा की जाने लगी नियमित किस्त एवं एजेंसी का पूरा पैसा जमा होने की बावजूद 15 अक्टूबर 2024 को ट्रैक्टर एजेंसी मालिक राजीव शुक्ला मुक्कू तिवारी एवं अन्य दो कर्मचारियों द्वारा मेरे घर से जबरदस्ती करते हुए और ये कहते हुए कि तुमने हमको पैसा जमा नहीं किया है ट्रैक्टर एवं ट्राली मेरे घर से लेकर चले गए , जब मैने चोला मंडलम अनुपपुर से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि एजेंसी वाले सर्विसिंग करवाने के लिए गाड़ी लेकर गए है , तब मैने अपने थाने रामनगर में शिकायत दर्ज करवानी चाही पर थाने में मेरा आवेदन नहीं लिया गया उसके बाद मैने हर जगह आवेदन दिया और 181 में भी शिकायत की पर आज दिनांक तक मेरा ट्रैक्टर एवं ट्राली मुझे नहीं मिला और न हीं एजेंसी मालिक पर कोई कार्यवाही हुई इस बीच मैने मीडिया का सहारा भी लिया जिसके बाद मेरा आवेदन तो थाने में लिया गया पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई जब भी थाने में जानकारी लेनी चाही तब कहा गया कि जांच चल रही है।

क्या ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक इतने दबंग है कि पुलिस विभाग एजेंसी मालिक पर कार्यवाही करने से कतरा रहा है, बहरहाल इन सारी घटनाओं को काफी समय बीतते जा रहा है पर कोई उचित कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही । रितेश तिवारी द्वारा थाने में लेनदेन संबंधित सभी कागज जमा करने के बाद भी कार्यवाही न होना या जांच में इतना समय लगना कही न कही पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में ल रहा है।

कलेक्टर ने नवंबर माह में सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में नवंबर माह में जारी सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में ए ग्रेड स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिसमें योजना सांख्यिकीय अधिकारी श्री डी.के. अहिरवार, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री बी.एस. परिहार, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक श्री के.के. सोनी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विनोद परस्ते, ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री जी.पी. गोस्वामी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एच.एस. धुर्वे, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. ए.पी. पटेल, परियोजना अधिकारी शहरी विकास श्री दिलीप कुमार पांडेय, परिवहन

अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह गौतम, सहकारिता विभाग की उपायुक्त श्रीमती सुनीता गोठवाल एवं उप संचालक कृषि श्री एन.डी. गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नागरिकों के शिकायतों के तुरंत संतुष्टिपूर्वक निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा 181 सीएम हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। जिसमें नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु शिकायत दर्ज कराई जाती है जिसका संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराया जाकर जारी रैंकिंग में ए ग्रेड स्थान प्राप्त किया गया। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए उपस्थित अन्य अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि अगली रैंकिंग में आप भी स्थान प्राप्त कर जिले की रैंकिंग को अव्वल ग्रेड पर लाएं।

आबकारी विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

5500 किलोग्राम महुआ लाहन मौके पर नष्ट व 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण के लिए आज वृत्त शाजापुर व्रत क्रमांक 1 में स्थित निपानिया कंजर डेरे पर दबिश देकर लगभग 5500 किलोग्राम महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया व 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 05 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक खत्री, मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, आबकारी उप निरीक्षक पंकज जैन, सुरेश पटेल, मीनाक्षी बोर्डिया आबकारी आरक्षक, दिनेश कौशिक, राकेश जमरा, अमित शर्मा सैनिक बाबूलाल गुर्जर, नरेंद्र, देवकरण व मोहन बड़ोदिया थाना बल का विशेष योगदान रहा।

किसी ने पत्नी द्वारा जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने तो किसी ने स्कूल द्वारा बच्चों की मनमानी फीस वसूलने की जनसुनवाई में शिकायत की

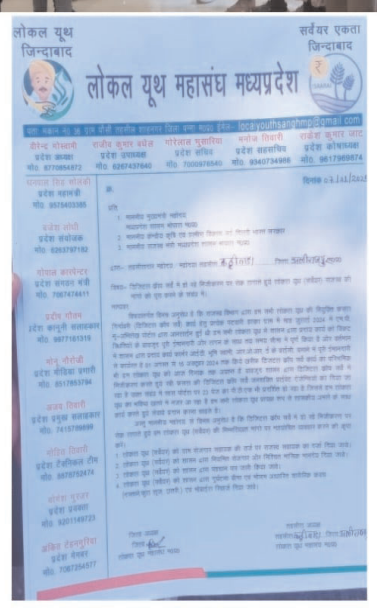

कट्ठीवाड़ा तहसील के सर्वेयरो(सहायक पटवारियों) ने अपनी मांगो को पुरा करने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया ।जिसमें डिजिटल क्राप एप के माध्यम से राजस्व विभाग का कार्य किया ।वह भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपनी जान जोखिम में डाल कर खेत खेत मे जाकर कार्य किया ।लेकिन उसका कोई भी जवाब या मानदेय नही मिला।

नर्मदापुरम

जनसुनवाई में डिलीवरी रूम बनाने , अवैध शराब भट्टी हटाने और शासकीय भूमि छल कपट से अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई

जनसुनवाई में कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए

आम जनों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए शासन के निर्देश अनुसार प्रति मंगलवार जनसुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाता है। आज आयोजित जनसुनवाई में 71 आवेदन प्राप्त हुए। आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर सोनिया मीना के समक्ष मूंडीमाता इटारसी के नर्मदा प्रसाद कहार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पत्नी दीपिका कहार ने उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उन्हें घर से निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है, तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देती है। वही नर्मदापुरम के गोलू सैनी ने एक निजी स्कूल की शिकायत करते हुए बताया कि उक्त निजी स्कूल में उनके पुत्र एवं पुत्री पढ़ाई करते हैं। स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूल की जा रही है, तथा उनके पुत्र व पुत्री को परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। उनके बच्चों को क्लासरूम से बाहर जमीन पर बैठाया जाता है तथा आए दिन स्कूलों में कार्यक्रमों एवं चैरिटी के नाम पर विद्यार्थियों से राशि वसूली की जाती है तथा विद्यार्थियों से घर से खाने पीने का सामान बुलवाया जाता है। उक्त स्कूल के शिक्षक शैक्षणिक कार्य करने में भी अयोग्य हैं जिस कारण विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार मय होता जा रहा है। प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संचालक बुद्धिस्ट ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम रानीपुर तवा बांध परियोजना के अंतर्गत ग्राम में 20 गांव शामिल हैं लेकिन आपातकालीन डिलीवरी रूम नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें 32 किलोमीटर दूर इटारसी जाना पड़ता है। कभी-कभी रास्ते में गर्भवती महिला की मृत्यु भी हो जाती है। संचालक बुद्धिस्ट ने तवा नगर में एक आपातकालीन डिलीवरी रूम बनाने एवं रूम में सभी सुविधाएं मुहैया कराने तथा शासकीय नर्स, स्टाफ, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। केसला के ग्राम भट्टी की सीमा वर्मा ने जनसुनवाई में प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनके ग्राम में अवैध शराब भट्टी है, जहां से अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है उन्होंने अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्राम गोची करौंदा तहसील इटारसी के बृजपाल सिंह ठाकुर ने प्रस्तुत शिकायती आवेदन में बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि को शासकीय कर शासकीय राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और इसका उन्हें मुआवजा भी प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने उपरोक्त आवेदनों पर उचित कार्रवाई करने का के निर्देश दिए। तहसील बाबई के ग्राम भटवाड़ा के मोहम्मद फिरोज खान ने खेती की जमीन का सीमांकन कार्य करने, इटारसी के अजमेर सिंह ने फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस जल्दी कराने में मदद करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। नर्मदापुरम के मुन्नालाल ने नाली दूरस्तीकरण करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया और बताया की नाली की साफ सफाई न होने के कारण नाली का पानी शासकीय क्वार्टर में आ जाता है जिससे बीमारी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम साकेत के बलराम सोलंकी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन में उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिस आवास में निवासरत हैं

वह क्षतिग्रस्त है और रहने की कही अन्य व्यवस्था उनके पास नहीं है। नर्मदापुरम के हरतीत ने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनकी माता जी का इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता था। किसी ने बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया। तत्संबंध में बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोहारिया कलां तहसील इटारसी के देवी प्रसाद ने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनके घर तक आने जाने के मार्ग पर कतिपय लोगों द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। उन्होंने रास्ता खुलवाने की मांग की। नर्मदापुरम की सावित्री अहिरवार ने बताया कि उनके पुत्र को दो-तीन लोगों ने मारपीट कर हाथ की हड्डी तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने सहायता प्रदान करने और कतिपय लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तुलसी नगर नर्मदापुरम के दिलीप बरेला ने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनकी कालोनी में आरसीसी रोड निर्मित नहीं है। कॉलोनी में बने रोड के मकान का गंदा पानी रोड पर निकास हो रहा है। जिन लोगों का पानी निकास हो रहा है उनसे कई बार बोलने पर भी पानी की निकासी बंद नहीं कर रहे हैं। जिससे सड़क पर पानी बहता रहता है। इससे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज आयोजित जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस एस रावत, अपर कलेक्टर श्री डीके सिंह, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बबीता राठौर सहित अन्य अधिकारियों ने भी जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई की।

ओझरा में 24 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा की तैयारियां जोरों पर

खरगोन कसरावद क्षेत्र के देव ग्राम ओझरां में आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से 17 जनवरी तक 24 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ, संस्कार महोत्सव एवं प्रज्ञा पुराण कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। यह चार दिवसीय कार्यक्रम शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में विद्वान मनीषियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर गायत्री प्रज्ञा पीठ ओझरां के गायत्री परिजन एवं ग्रामवासियों द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गायत्री प्रज्ञा पीठ ओझरां के व्यवस्थापक हरिराम पटेल ने बताया कि इस तहसील स्तरीय आयोजन के लिए गांव-गांव बैठकें लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन भव्य कलश एवं सद्ग्रंथ शोभायात्रा के माध्यम से आयोजन का शुभारंभ होगा। कलश यात्रा के लिए पूरे क्षेत्र में निमंत्रण दिया जा रहा है। अहिल्यापुरा के सक्रिय कार्यकर्ता बलीराम पटेल ने बताया कि 24 कुण्डीय यज्ञशाला के निमार्ण का कार्य इन दिनों द्रुतगति से चल रहा है। इसके लिए रंजना पटेल, प्रमीला पटेल, जयमाला पटेल, ऋतु पटेल, मिश्रीलाल यादव, दुलीचंद यादव, गोपीचंद पटेल, अशोक यादव आदि कार्यकर्ता भाई- बहनों की टोली कार्यक्रम स्थल पर नियमित श्रमदान में जुटी हुई है। गांव के युवाओं ने बताया कि इस आयोजन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। सभी अपने अपने स्तर से आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। गायत्री साधकों ने बताया कि यज्ञशाला और भव्य प्रवचन पांडाल के साथ ही यहां युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के जीवन पर आधारित विशाल प्रदर्शनी, उनके द्वारा रचित युग साहित्य स्टाल, समाधि स्थल (प्रखर प्रज्ञा-सजल श्रद्धा), जवारों से सुसज्जित भारत माता, मशाल एवं गुरुजी-माताजी के चित्र भी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षक का केंद्र होंगे। युवा कार्यकर्ता मुरारी पटेल ने बताया कि कार्यक्रम के पूर्व 10 जनवरी को जन जागरण के उद्देश्य से मशाल यात्रा भी गांव में निकाली जाएगी। उन्होंने युवा कार्यकर्ता भाई बहनों से इस मशाल रैली में भागीदारी की अपील की है।

कलेक्टर ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर बांड ओवर की कार्यवाही करने के निर्देश

खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एसडीएम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों, उपयंत्री, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्य अधिकारियों एवं जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर नल जल योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएस अचाले भी उपस्थित थे। बैठक में विकासखंडवार जल जीवन मिशन की प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देशित किया गया कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी है उन्हें पंचायतों को शीघ्र हस्तांतरित किया जाए। इसके साथ ही पूर्ण हो चुकी योजनाओं में नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के

आधार नंबर पोर्टल पर एंट्री की जाए। जो योजनाएं 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें जनवरी माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए। 15 मार्च तक जिले की जल जीवन मिशन के सभी योजनाएं पूर्ण होकर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो जाना चाहिए। जल जीवन मिशन की योजनाओं में किसी भी तरह के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। समीक्षा के दौरान नल जल योजना के निर्माण में धीमी प्रगति पाए जाने पर पंत एंटरप्राइजेज, नर्मदा कंस्ट्रक्शन के अभिजीत पंडित, रूद्र कंस्ट्रक्शन के अरुण रावत, खरगोन के दिलीप पाटीदार, पीवी एसोसिएट्स के चंदू नांदनिया के विरुद्ध बांड ओवर की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया गया कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध बंध पत्र भरवाए। नल जल योजनाओं के निर्माण के दौरान जिन सड़कों को क्षति पहुंची है उनका मरम्मत व सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिए गए और यह कार्य तभी पूर्ण माना जाएगा। जब संबंधित विभाग यह प्रमाण पत्र दे देगा कि उसकी सड़क ठीक कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत खरगोन जिले में 778 नल जल योजनाएं स्वीकृत है। इनमें से 513 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 263 योजना का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 380 योजनाएं ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है।

कलेक्टर ने किया जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने डाइट कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां छात्र- छात्राओं द्वारा गणित विषय के 14, विज्ञान विषय के 13, पर्यावरण विषय के 11 एवं सामाजिक विज्ञान विषय के 35 उत्कृष्ट मॉडल बनाये गये हैं। कलेक्टर ने इन मॉडलों का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि विकासखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में चयनित माध्यमिक विद्यालय के 97 एवं हाई स्कूल के 16 प्रतिभागियों द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल हुए। उन्होंने गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल, मंचीय विद्या लघु नाटिका, सेमिनार लघु गायन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में कम्प्यूटेशनल सोच, इतिहास, कृषि, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, कृषि, भूगोल, स्वास्थ्य, सामाजिक राजनीतिक जीवन, संचार, परिवहन विषय पर उत्कृष्ट मॉडल और स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन के लिए मोटा अनाज (श्रीअन्न) पर सेमिनार में 14, लघु नाटिका में नारी सशक्तिकरण, बाजार के बदलते स्वरूप, बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संस्कृति विविधता एवं अन्य 12 लघु नाटिका और लघु गायन में 14 विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय स्वरचित गीत में सहभागिता की। मॉडल एवं सभी विधाओं के लिए व्याख्याता डाइट श्री संजय शर्मा, जीएल उप्रैलिया, शैलेश वर्मा निर्णायक रहे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल व्यौहार ने कहा कि विद्यालय स्तर से ही प्रतिभा को उजागर करने का अवसर मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इस प्रकार के आयोजन में अवश्य प्रस्तुत करें। योजना अधिकारी श्री जीके नायक ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट से अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर सहायक नोडल अधिकारी विकासखंड स्त्रोत समन्वयक श्री ओपी राय, एपीसी श्री समीर त्यागी, श्री आनंद शर्मा, बीएसी श्री ब्रजेश नेमा, सीएसी श्री प्रदीप मेहरा, श्री मधुसूदन दुबे, श्री राजकुमार, श्री राजेश, श्री संजय मेहरा, श्री संदीप भारिया सहित मार्गदर्शी शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसोदा में शिविर संपन्न

धार/मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान (जन कल्याण पर्व) के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसोदा में शिविर का आयोजन रखा गया! जिसमें शासन के विभिन्न विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका मिशन, पशु चिकित्सालय, स्वरोजगार आदि विभाग के अधिकारी उपस्थित होकर संबंधित विभाग के आवेदन लिए गए ।ग्रामीणों ने नालिया एवं मच्छर जैसे समस्या बता कर उनके भी आवेदन दिए। साथ ही राजस्व विभाग के पटवारी व ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि केवाईसी, व समग्र केवाईसी भी की गई। इस

अवसर पर शिविर नोडल स्वाति भूरिया (एनआरएलएम), पुष्पा परमार (ग्राम सेवक) ,अमर सिंह अखाड़े (पटवारी), प्रमोद सिंह (कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर), वर्षा जैन (आर सेठी),उमेश अलासिया (पशु चिकित्साक), चन्दर मसार (सचिव),अशोक बारिया (सरपंच प्रतिनिधि), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित हुए।

जन्म दिवस पर बुध्दि के ढक्कन खोले

उज्जैन

जन्म दिवस के अवसर पर हमें ओर हमारे सभी अनुयायियों और अपने से छोटों को अपनी सनातन संस्कृति के अनुरूप जन्म दिवस मनाते हुए ओर मंदिरों पर जाना, बड़े बुजुर्गों के साथ गुरुओं के दर्शन पूजन करना चाहिए यही पद्धति सही है ! जन्म दिवस के अवसर पर अपनी बुद्धि का ढक्कन खोलना

चाहिए और अच्छे संस्कारों का उसमें समावेश करना चाहिए यह बात केसरिया में चल रहे नौ कुंडिया पंच दिवसीय श्रीराम मारुति महा यज्ञ के प्रथम दिवस श्रीगुरूजी रविराजजी उपाध्याय (चंदोडिया वाले) ने पर्वतसिंह सोलंकी ओर जालमसिंह राजपुत के जन्म दिवस के अवस पर कही ! केसरिया ने श्रीराम मारुति महायज्ञ का आयोजन 7 जनवरी पोश मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ हुआ जो 11 जनवरी पोस माह की शुक्ल पक्ष की 12 को होगा !

महाकुंभ वेबसाइट पर 83 देशों के 33 लाख से ज्यादा लोगों की विजिट

नेशनल डेस्क. उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बताया कि दुनिया भर के 183 देशों के लोग महाकुंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न वेबसाइटों और पोर्टलों का उपयोग कर रहे हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट, *https://kumbh.gov.in/*, ने विश्वसनीय जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिस पर लाखों उपयोगकर्ताओं का भारी ट्रैफ़िक देखा जा रहा है। यह जानकारी सरकार ने सोमवार को जारी की।

इसमें बताया गया कि वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 4 जनवरी तक 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने महाकुंभ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया। इनमें यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों से आए आगंतुक भी शामिल हैं, जो इस आयोजन की वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है। पोर्टल का प्रबंधन करने वाली तकनीकी टीम के एक सदस्य ने पुष्टि की कि 4 जनवरी तक कुल 33,05,667 उपयोगकर्ताओं ने आधिकारिक महाकुंभ वेबसाइट पर विज़िट किया, और यह आंकड़ा 183 देशों से आया है, जिनमें दुनिया भर के 6,206 शहरों से विज़िट्स दर्ज की गई हैं वेबसाइट पर विज़िट के मामले में भारत अब तक सबसे ऊपर है, इसके बाद संयुक्त राय अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से भी महत्वपूर्ण ट्रैफ़िक आ रहा है। बयान में कहा गया है कि आगंतुकों ने केवल वेबसाइट पर विज़िट नहीं किया, बल्कि इसके कंटेंट को देखने में भी काफी समय बिताया है। तकनीकी टीम ने बताया कि वेबसाइट के लॉन्च के बाद से ट्रैफ़िक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और जैसे-जैसे महाकुंभ का आयोजन नज़दीक आ रहा है, दैनिक उपयोगकर्ताओं की संख्या अब लाखों तक पहुँच चुकी है, बयान में कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनमें महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट भी शामिल है, जिसे 6 अक्टूबर, 2024 को प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया था।

गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर 12 गाड़ियों का काफिला

दिखावे के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा कानपुर का गैंगस्टर अजय ठाकुर

नेशनल डेस्क. शहर में एक बार फिर कानून का राज कायम करने की दिशा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया है। अजय ठाकुर को अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर 12 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर में हंगामा करते हुए पकड़ा गया। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला करने और आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

जानिए क्या था पूरा मामला?

कुछ दिन पहले शहर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दर्जन भर लग्जरी गाड़ियां स्टंट करते हुए राहगीरों में भय का माहौल पैदा कर रही थीं। इन गाड़ियों पर काली फिल्म लगी थी, नंबर प्लेट गायब थी और हूटर बज रहा था। आगे चल रही स्कॉर्पियो में गैंगस्टर अजय ठाकुर बैठा था, वहीं बगल में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी। गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने निकला था। यह काफिला कानपुर के डीसीपी साउथ ऑफिस के पास से भी गुजरा। इस दौरान भी स्टंटबाजी जारी रही। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू किए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अजय ठाकुर पर शिकंजा कस दिया।

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस जब अजय ठाकुर के ठिकाने पर पहुंची तो उसने छज्जे पर लटककर आत्महत्या की धमकी दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने पुलिसकर्मियों से भिड़ गया। ईंट उठाकर उनपर हमला कर दिया। आखिर में जब भागने में असफल रहा तो अपने सिर पर ईंट मारकर खुद को ही घायल कर लिया। हालांकि, पुलिस के सामने उसकी एक ना चली। बर्रा थाने की पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

पहले भी अजय ठाकुर पर दर्ज हैं कई मुकदमे

सड़कों पर भौकाल दिखा रहे अजय के ऊपर दो दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिला बदर होने के बाद भी वह जिले के अंदर घूम रहा था। ऐसे में उसपर नई एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें पुलिस पर हमला करना, आत्महत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालना आदि शामिल है।

कौन है अजय ठाकुर?

अजय ठाकर का नाम कानपुर के दबंग गैंगस्टरों में गिना जाता है। करीब दो साल पहले वह एक डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी के शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। तब इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अजय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। हालांकि, उसकी बहन और मां ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर दावा किया था कि अजय को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने इस कार्रवाई से शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का एक संदेश दिया है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या खतरे में इस्लाम?

महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर छिड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस, मौलाना का विवादित बयान चर्चा में

भारत में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला, इस बार मुसलमानों की भागीदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। प्रयागराज में इस महीने शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर कुछ संगठनों ने मुसलमानों के प्रवेश पर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों के धर्मांतरण की आशंका जताई। इसके बाद, रजवी ने मुसलमानों को महाकुंभ में न जाने की सलाह दी। हालांकि, रजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद द्वारा मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग का विरोध किया था।

वहीं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले पर विरोध किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी मेला या धार्मिक स्थल को देखने से मुसलमानों का धर्मांतरण हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मुसलमान महाकुंभ में ज्ञानवर्धन के लिए जाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।अखाड़ा परिषद और अन्य हिंदू संगठन महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

कुछ हिंदू नेता, जैसे बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ने भी इस कदम का समर्थन किया है। इस विवाद ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धार्मिक सहिष्णुता और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए भारत से मुसलमानों को धार्मिक आयोजन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार देने की अपील की है।रजवी ने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराने की योजना हो सकती है, और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखा है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को इस आयोजन से दूर रहने की सलाह दी गई थी, ताकि वे किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। जमीयत उलमा-ए-हिंद के मौलाना काब रशीदी ने कहा कि इस प्रकार के बयान संविधान के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और महाकुंभ में मुसलमानों को प्रतिबंधित करने की बात संविधान की भावना के खिलाफ है।

पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी हो रही सच ! रेगिस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर मक्का-मदीना में रेड अलर्ट

सऊदी अरब के प्रमुख शहरों, मदीना , जेद्दा और मक्का में अचानक आई भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है। इस मौसमीय बदलाव के चलते सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इन शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है, और यह बदलाव जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सोमवार से शुरू हुई बारिश बुधवार तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। सऊदी अरब के कई बड़े शहरों में शुरू हुई बारिश के बाद क्षेत्र के मौसम में असामान्य बदलाव देखने को मिला है। सऊदी के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने मक्का, रियाद, मदीना, अल-बाहा और तबुक क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मदीना में आई बाढ़ के कारण यातायात में अड़चनें आ रही हैं और कई जगहों पर जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब के लोग इस बदलाव को देखकर चौंक गए हैं, क्योंकि इस देश को आमतौर पर सूखा और रेगिस्तानी इलाका माना जाता है। इस बदलाव को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। सऊदी अरब में भी, जो कभी मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाका था, अब यहां की धरती पर हरी घास और पौधे उगते हुए दिख रहे हैं।

इस असामान्य मौसमीय बदलाव को लेकर कुछ लोग इसे पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, पैगंबर मोहम्मद ने 1400 साल पहले यह कहा था कि कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक अरब की भूमि घास के मैदानों और नदियों में नहीं बदल जाएगी। साथ ही, पैगंबर ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कयामत से पहले लोगों के पास इतना धन होगा कि कोई जकात लेने वाला नहीं मिलेगा। सऊदी अरब में बाढ़ और रेगिस्तान में हरियाली की स्थिति ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। लोग इन घटनाओं को पैगंबर की भविष्यवाणी से जोड़ते हुए यह मान रहे हैं कि यह कयामत की निशानियों में से एक हो सकता है। इस्लामिक समुदाय के कई लोग इसे एक धार्मिक चिह्न के तौर पर देख रहे हैं और मान रहे हैं कि कयामत का दिन करीब है।

मदीना, मक्का, और जेद्दा में सड़कों पर जलभराव

सऊदी अरब में आई बारिश और बाढ़ के कारण मदीना, मक्का, और जेद्दा में काफी असुविधा उत्पन्न हुई है। मदीना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया है और लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मक्का में तीर्थयात्रियों को भी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है।

पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी के साथ जुड़ी यह घटनाएँ सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं। कुछ लोग इसे एक चमत्कारी घटना मान रहे हैं,

जबकि कुछ अन्य इसे प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन का असर

जहां एक ओर धार्मिक दृष्टिकोण से इसे एक अहम घटना माना जा रहा है, वहीं विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप मौसम के पैटर्न में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब के मौसम में अचानक बदलाव इस तथ्य का प्रतीक हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन दुनियाभर में असर डाल रहा है और इसे भविष्य में और अधिक महसूस किया जाएगा। मक्का और मदीना में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं, और उन्हें इस समय भारी बारिश और बाढ़ के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें इस प्रकार की घटनाओं का सामना कभी नहीं हुआ। इस्लामिक समुदाय के कुछ लोग इसे कयामत की निशानी मानते हुए इसे एक सिग्नल के रूप में देख रहे हैं।

प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज सातवां दिन प्रमुख सहयोगियों ने समाप्त करने का किया अनुरोध

पटना. बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज सातवां दिन है। किशोर को गहन चिकित्सा जांच के लिए मंगलवार को पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद भी उनका अनशन जारी है। वे अनशन नहीं तोड़ने पर की जिद्द पर अड़े हुए हैं। आमरण अनशन कर रहे किशोर को संक्रमण, निर्जलीकरण, कमजोरी और बेचैनी की समस्या है।

पीके के प्रमुख सहयोगियों ने बिहार सरकार पर साधा निशाना

यहां की एक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद उन्हें बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया। जनसुराज पार्टी के नेताओं पवन के वर्मा और वाई वी गिरि ने पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक रविशंकर सिंह की मौजूदगी में किशोर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी दी। वर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीपीएससी उम्मीदवारों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने की उनकी ''अनिच्छा उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ''वह (नीतीश) राज्य के अभिभावक हैं, लेकिन विरोध करने वाले उम्मीदवारों से मिलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने प्रशांत किशोर से सामान्य भोजन लेने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर विचार करने को कहा है।

आमरण अनशन समाप्त करने का किया अनुरोध

वर्मा ने कहा कि उनकी लड़ाई सराहनीय है, लेकिन बिहार कई समस्याओं का सामना कर रहा है और लंबे संघर्ष के लिए उनके लिए अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक रविशंकर सिंह ने कहा, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वह सामान्य भोजन लेना शुरू करें, जिससे उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। अगर उनकी हालत में सुधार होता है, तो उन्हें कल आईसीयू से बाहर लाया जा सकता है...लेकिन उन्हें छुट्टी दिए जाने का अभी सवाल ही नहीं उठता। पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता गिरि ने कहा, कार्यपालिका बीपीएससी उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने में बुरी तरह विफल रही है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे विधायिका हल कर सके। इसलिए अब हमें न्यायपालिका के शरण में जाना चाहिए। मैं अपने 52 साल के कानूनी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हम जल्द राहत की उम्मीद कर सकते हैं।

ट्रंप ने फिर दोहराया- आर्थिक बल से कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाकर रहेंगे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा को अमेरिका का भाग बनाने के लिए ''आर्थिक बल का प्रयोग करेंगे। ट्रंप की इस टिप्पणी पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। फ्लोरिडा के 'मार-ए-लागो (ट्रंप का निजी रिजॉर्ट एवं क्लब) में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह कनाडा को देश के अधीन करने और उसे हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने कहा, ''नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वह कनाडा को अमेरिका का हिस्सा और उसका 51वां राय बनाना चाहते हैं। कई बार वे ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर कह चुके हैं। ट्रंप ने कहा, ''मैं आर्थिक बल का उपयोग करूंगा क्योंकि कनाडा और अमेरिका के लिए यह वास्तव में एक बड़ी बात होगी। आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बेहतर होगा। मत भूलिए, हम मूल रूप से कनाडा की रक्षा करते हैं। ट्रूडो ने एक दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। ट्रूडो ने कहा, ''एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने के नाते दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है। ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका अब कनाडा को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, ''मैं कनाडा के लोगों से प्यार करता हूं, वे महान हैं। लेकिन हम इसे बचाने के लिए हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम कनाडा की देखभाल के लिए हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम व्यापार घाटे में भारी नुकसान उठा रहे हैं। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, वे हमारी 20 प्रतिशत कारें बनाते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है।

ट्रंप ने कहा, ''वे हमें जो लाखों कारें भेजते हैं उससे वे बहुत पैसा कमाते हैं। वे हमें बहुत सी अन्य चीजें भेजते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है और हमें अन्य उत्पादों की भी जरूरत नहीं है। हमें उनके दूध की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा दूध है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमें इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा, ''मैंने कहा कि अगर आप एक राय बनते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरे देश हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे। ईयू के साथ हमारा व्यापार घाटा 350 अरब अमेरिकी डॉलर है। वे हमारी कारें नहीं लेते, वे हमारे कृषि उत्पाद नहीं लेते, वे कुछ भी नहीं लेते। इसलिए, हम उनके साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569